

BRIEF NEWS

साहिबगंज में गंगा फेरी के टेंडर को हाईकोर्ट में चुनौती

RANCHI : साहिबगंज अवेध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय के गवाह अंकुश राजहंस यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को गंगा नदी पर फेरी टेंडर को चुनौती दी है। कोर्ट ने अंकुश यादव की याचिका को स्वीकार करते हुए 18 जून को मामले की सुनवाई निर्धारित की है। गंगा नदी पर फेरी के लिए टेंडर 19 जून को होना है। अंकुश ने याचिका में कहा है कि साहिबगंज जिला प्रशासन खनन माफिया के सिंडिकेट को लाभ देने के लिए जबरन नियमों को बदल रहा है। नियमों में जो बदलाव किए गए हैं, उससे किसी खास व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की तैयारी है। इस मामले की जल्द सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के समक्ष अधिवक्ता पार्थ जालान ने आग्रह किया। इसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

रेलवे टिकट की कालाबाजारी करने का आरोपी गिरफ्तार



RANCHI : रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की अपराध शाखा ने रेलवे टिकट की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सुखदेव नगर पुलिस की सहायता से रांची के राउर रोड स्थित सिद्धांत इंटरप्राइजेज में छापेमारी कर शशिकुमार यादव को गिरफ्तार किया। इसके पास से 14 रेलवे का ई-टिकट बरामद किया गया है। बरामद टिकट का मूल्य 19 हजार 600 रुपये है। इस संबंध में आरपीएफ रांची के निरीक्षक प्रभारी दिगंजय शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही टिकट भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपित ने अपना अपराध स्वीकार किया है। उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 143 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

आइएएस चंद्रशेखर केंद्र में संयुक्त सचिव पद के लिए मनोनीत

RANCHI : भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और राज्य एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव चंद्रशेखर को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए इंग्लैंड भेजा गया है। केंद्र सरकार ने संयुक्त सचिव पद के लिए मनोनयन किया है लगभग 65 अफसर पूरे देश भर से लिए जा रहे हैं। संयुक्त सचिव के पद पर भारत सरकार में योगदान देंगे। जल्दी कार्मिक विभाग में नियुक्ति करने की तैयारी करेगा। इस संबंध में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है।

15 नवंबर तक एक लाख कुआं निर्माण का टारगेट

RANCHI : राज्य सरकार ने 15 नवंबर तक हर हाल में एक लाख कुआं का निर्माण का लक्ष्य ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बिरसा सिंचाई कृषि संवर्धन योजना की समीक्षा की है, यह पाया कि कुआं निर्माण की यह योजना काफी धीमी चल रही है। इसके काम में तेजी लाने को कहा गया है। सभी जिलों व प्रखंड-पंचायत स्तर पर अधिकारियों को कहा गया है कि वे लोगों को संपर्क करके काम में तेजी लायें। सीएम ने इसके अलावा बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पीछे लगाने के साथ उसके रख-रखाव एवं संरक्षण की पूरी व्यवस्था भी करने को कहा है।

जमीन घोटेला मामले में ईडी ने अदालत में फाइल की चार्जशीट एएसएआर कोर्ट में ऑनलाइन के बदले किया ऑफलाइन आवेदन

PHOTON NEWS RANCHI : जमीन घोटेला मामले में ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दिया है। चार्जशीट में ईडी ने दावा किया है कि सात अगस्त 2023 को हेमंत सोरेन को पहला समन जारी कर 14 अगस्त 2023 को बुलाया गया था। ठीक इसके बाद 16 अगस्त 2023 को आरोपी राजकुमार पाहन ने संबंधित जमीन पर दावेदारी का आवेदन डीसी ऑफिस में डाल दिया। इसके बाद 9 जनवरी 2024 को एएसएआर कोर्ट ने एएसएआर केस नंबर 81/23-24 के तहत 29 जनवरी को आदेश जारी कर 1978 से 1989 के बीच हुए सारे जमाबंदी को कैमिल कर जमीन का मालिक राजकुमार पाहन को बना दिया। ईडी का कहना है कि इस मामले में जांच के दौरान जब स्पेशल रेगुलेशन ऑफिसर से पूछा गया कि संबंधित जमीन को लेकर कब ऑनलाइन आवेदन हुआ था तो ऑफिसर ने बताया कि यह आवेदन ऑफ लाइन आया था। जबकि साल 2023-24 में जमीन से जुड़े सारे आवेदन ऑन लाइन आए थे। अब सवाल है कि एक ऑफ लाइन आवेदन का निपटारा महज 20 दिन के भीतर कैसे कर दिया गया। जबकि उस साल कुल 103 केस दर्ज हुए थे, जिनमें से राजकुमार पाहन से जुड़े मामले समेत कुल चार केस का निपटारा



फर्जी डीड से हड़पी गई 6.34 एकड़ जमीन

ईडी का दावा है, कि जांच के दौरान साल 1940 में बना फर्जी डीड नंबर 3985 का पता चला, जिसे भानु के अन्य सहयोगियों ने तैयार किया था। इस डीड के जरिए बलाक पाहन को विक्रेता और असगर हुसैन को क्रेता दिखाया गया था। इस फर्जी डीड के

जरिए 6.34 एकड़ जमीन हड़पी गई। इसी जमीन के प्लॉट संख्या 989 के तहत 0.84 एकड़ और प्लॉट संख्या 996 के तहत 0.32 एकड़ जमीन भी हेमंत सोरेन के कब्जे में हैं। ये प्रॉपर्टी 8.86 एकड़ का ही हिस्सा है।

जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा से तीन दिनों तक राज उगलवाएगी जांच एजेसी, कोर्ट ने दी रिमांड

RANCHI : जमीन घोटेला मामले में गिरफ्तार जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा से ईडी तीन दिनों तक पूछताछ करेगी। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने ईडी को पूछताछ के लिए शुक्रवार को तीन दिनों की रिमांड की अनुमति दी है। ईडी की ओर से उससे पूछताछ की आवश्यकता बताते हुए सात दिनों की रिमांड देने का आग्रह किया गया था। इससे पूर्व गत गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में पेश किया था। पेशी के दौरान ईडी के अधिवक्ता ने कोर्ट से शेखर कुशवाहा को रिमांड पर लेकर पूछताछ की



अनुमति मांगी थी। इसका बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने विरोध किया। कोर्ट ने शेखर कुशवाहा को न्यायिक हिरासत में हॉटवर स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार जेल भेज दिया था। अदालत ने रिमांड पर शुक्रवार को सुनवाई की और तीन दिनों की रिमांड की मंजूरी प्रदान की। उल्लेखनीय है कि ईडी ने जमीन घोटेला मामले में शेखर

कुशवाहा को बुधवार को गिरफ्तार किया था। ईडी की जांच में यह बात सामने आयी थी कि शेखर कुशवाहा ने प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह, इरशाद अंसारी, अफसर अली सहित अन्य के साथ मिलकर 1971 का फर्जी डीड बनाया था। बड़गाई अंचल के तत्कालीन अंचल राज्य उपनिरीक्षक भानु प्रताप के साथ

मिलकर उसने बरियतू की 4.83 एकड़ की जमीन के रयत जिनुआ भोका का नाम बदल कर समरेंद्र चंद्र घोषाल के नाम की ड्रीटी कर गैरमजरूआ जमीन को सामान्य खाते की जमीन में बदल दिया था। इसके बाद 22.61 कोरड की जमीन को 100 कोरड से अधिक कीमत में बेचने की तैयारी थी। ईडी गिरोह के सभी सदस्यों को पूर्व में ही जेल भेज चुकी है। ईडी बीते कुछ दिनों से लगातार शेखर को पूछताछ के लिए बुला रही थी लेकिन वह पूछताछ में ईडी का सहयोग नहीं कर रहा था। ईडी ने पहली बार 22 अक्टूबर, 2023 को और दूसरी बार 16 अप्रैल, 2024 को शेखर कुशवाहा के ठिकानों पर छापेमारी की थी।

किया गया। ईडी के मुताबिक सारा खेल यह दिखाने के लिए किया

गया कि संबंधित 8.86 एकड़ जमीन राजकुमार पाहन की थी ना

कि हेमंत सोरेन की। ईडी के मुताबिक सारा खेल हेमंत सोरेन

के इशारे पर किया गया ताकि केस के प्रभावित किया जा सके।

रात 11 से सुबह 6 बजे तक रहेगी ड्यूटी, पूरे शहर पर रखनी होगी नजर पुलिस अधिकारियों की लगी नाइट शिफ्ट, देर रात होने वाले क्राइम पर कंट्रोल की कवायद

CRIME REPORTER RANCHI : राजधानी रांची में लेट नाइट होने वाले अपराध की घटनाओं पर ब्रेक लगाने के लिए अब शहर में पदस्थानित डीएसपी नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में एक सप्ताह के लिए एक डीएसपी की नाइट शिफ्ट लगाई गई है। राजधानी में अपराध की वारदातों पर ब्रेक लगाने के लिए पहली बार डीएसपी स्तर के अधिकारियों से नाइट शिफ्ट करवाया जा रहा है। डीएसपी स्तर के अधिकारियों को नाइट शिफ्ट के दौरान रांची के कचहरी स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में उपस्थित रहना है। रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे सुबह तक डीएसपी कंट्रोल रूम में नाइट शिफ्ट कर रहे हैं। रांची में पदस्थानित प्रत्येक डीएसपी को एक सप्ताह तक नाइट ड्यूटी करनी है, इस दौरान उन्हें कंट्रोल रूम से पूरे शहर पर नजर रखना है। कौन डीएसपी पुलिस कंट्रोल रूम में कब नाइट शिफ्ट करेगा इसके लिए बाकायदा रोस्टर बनाया गया है। रांची के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया यह देखा जा रहा था कि रात के समय सूचनाओं मिलने के बावजूद पुलिस का रिस्पांस टाइम बेहतर नहीं हो पा रहा था। ऐसे में यह जरूरत थी की एक सीनियर अधिकारी को पुलिस कंट्रोल में

- स्थायी तौर पर एडिशनल एसपी की तैनाती
- रांची में पदस्थानित प्रत्येक डीएसपी को एक सप्ताह तक करनी होगी नाइट ड्यूटी
- हर सूचना पर करना होगा रिपॉर्ट



कचहरी स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में सीसीटीवी मॉनिटर करते पुलिसकर्मी।

ज्वेलरी शॉप में लूटकांड का मामला : घटनास्थल पर पहुंचे बन्ना गुप्ता भयमुक्त होकर करें व्यवसाय, सरकार देगी पूरी सुरक्षा, अपराधी जल्द होंगे गिरफ्तार

RANCHI : पंडरा ओपी क्षेत्र के इटकी रोड स्थित बन्ना में पंचवटी ज्वेलरी शॉप में अपराधियों ने गुरुवार की लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस मामले में कार्रवाई करने में जुटी है। इस बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पीड़ित ज्वेलरी कारोबारी से शुक्रवार को मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि अपराधियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि अन्य अपराधियों में कानून का डर पैदा हो। मुख्यमंत्री ने राज्य की कानून व्यवस्था



को लेकर कई सख्त निर्देश भी जारी किए हैं, जिनका अनुपालन किया जा रहा है। साथ ही मौके पर उपस्थित सिटी एसपी को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द मामले का खुलासा कर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल

भेजें। मंत्री ने पुलिस गश्ती बढ़ाने, अपराधियों पर नकेल लगाने, नशाखोरी रोकने, रात्रि गश्ती तेज करने और अपराधमुक्त रांची बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने का भी निर्देश दिया।

तैनात किया जाए, ताकि पुलिस का रिस्पांस समय बढ़िया हो, इसी को ध्यान में रखते हुए रांची के

सभी डीएसपी से रोस्टर के आधार पर एक सप्ताह के लिए नाइट शिफ्ट करवाया जा रहा है। इस

दौरान पूरी रात डीएसपी कंट्रोल रूम से पूरे शहर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

सुपरवाइजर घर-घर जाकर बीएलओ के कार्यों का करें सत्यापन : सीईओ



PHOTON NEWS RANCHI : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) के. रवि कुमार ने लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की प्राप्ति शिकायतों पर हो रही कार्रवाई के लिए सभी जिलों के निर्वाचन संबंधी पदाधिकारियों के साथ निर्वाचन सदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुक्रवार को समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि लोक सभा निर्वाचन के दौरान मतदाता सूची से गलत विलोपन की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनका नियमानुसार सत्यापन करते हुए कार्रवाई करना

सुनिश्चित किया जाए। सीईओ ने कहा कि वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप के आवंटन के क्रम में बचाये गए एएसडी सूची से मिलान करते हुए मतदाता सूची से शिफ्टेड, डुप्लिकेट एवं मृत मतदाताओं का नियमानुसार विलोपन करें। अभी भी जिन मतदाताओं के पास पुराना लेमिनेटेड मतदाता पहचान पत्र है, उसे बदलते हुए नए रंगीन मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही किसी भी कारण अब तक छूटे मतदाताओं को भी मतदाता सूची से जोड़ने का कार्य किया जाए।

राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति के साथ बादल पत्रलेख ने की बैठक 'किसानों के दो लाख तक ऋण होंगे माफ'

PHOTON NEWS RANCHI : कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल ने कहा कि किसानों के दो लाख रुपये तक के लोन माफ किये जाएंगे। 31 मार्च, 2020 तक किसानों द्वारा लिया गया 50 हजार से लेकर दो लाख तक के ऋण को वन टाईम सेंटलमेंट के माध्यम से माफ किया जाएगा। इसके लिये सभी बैंकों से प्रस्ताव आमंत्रित किया गया है। बादल शुक्रवार को नेपाल हाउस स्थित सभागार में राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति के पदाधिकारियों के साथ केसीसी लोन सहित कृषि कार्य के लिए किसानों के जरिये लिए गये ऋण की माफी योजना को लेकर बैठक में बोल रहे थे। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वादे के मुताबिक ऐसे



बैठक करते कृषि मंत्री बादल पत्रलेख।

किसानों को राहत दी है, जो बैंक ऋण की वजह से चिंताग्रस्त रहते थे। राज्य के करीब 4 लाख 73 हजार से ज्यादा किसानों के 50 हजार रुपये तक के ऋण माफ किये जा चुके हैं। इस मद में सरकार के जरिये 1900 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि बैंकों को दी गयी है।

बड़ा तालाब पूरी तरह प्रदूषित, सफाई के नाम पर खानापूर्ति करने का आरोप पानी से उठ रही दुर्गंध से बीमारी फैलने का खतरा

PHOTON NEWS RANCHI : इन दिनों रांची के बड़ा तालाब की स्थिति बेहद खराब हो गई है। बड़ा तालाब के पानी से उठने वाली दुर्गंध के कारण आसपास रहने वाले लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। हालात यह है कि तालाब के पास से गुजरने में भी लोगों को सोचना पड़ता है। पानी से इतना खराब दुर्गंध आता है कि कई बार लोग गश्त खाकर गिर जाते हैं। वहीं बड़ा तालाब की स्थिति को देखते हुए स्थानीय लोग सत्याग्रह पर उतर गए हैं। पिछले कई दिनों से पानी से आ रही दुर्गंध की वजह से लोगों ने निर्णय लिया कि यदि अब जिला



प्रशासन और नगर निगम कोई संचान नहीं लेता है तो आम लोग सत्याग्रह कर जिला प्रशासन को नौद दे जालाने का काम बचाओ अभियान समिति के संरक्षक राजीव रंजन मिश्रा बताते हैं कि नगर निगम के अधिकारियों

से स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत की है, लेकिन नगर निगम के लोग तालाब सफाई के नौद दे जालाने का काम बचाओ अभियान समिति के संरक्षक राजीव रंजन मिश्रा बताते हैं कि नगर निगम के अधिकारियों

को लेकर कई सख्त निर्देश भी जारी किए हैं, जिनका अनुपालन किया जा रहा है। साथ ही मौके पर उपस्थित सिटी एसपी को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द मामले का खुलासा कर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजें। मंत्री ने पुलिस गश्ती बढ़ाने, अपराधियों पर नकेल लगाने, नशाखोरी रोकने, रात्रि गश्ती तेज करने और अपराधमुक्त रांची बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने का भी निर्देश दिया।

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड मुक्ति मोर्चे के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीट का मामला उठाया। उन्होंने सीबीआई के साथ ही ईडी जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि देश में लोकसभा का परिणाम निकला और नीट का रिजल्ट भी निकला। फिर अचानक मालूम चला कि रांची के एक परीक्षार्थी को 720 में 720 नंबर मिला। हमारे लिए यह गर्व का विषय था। लेकिन कुछ ही देर बाद 720 और 719 का जो फिनर सामने आया तो पूरा देश दंग रह गया। कुछ लोग चुनाव के अपा धापी में भूल गये थे कि उस



वक्त बिहार में, गुजरात, राजस्थान में तीन भाजपा शासित राज्य में इन तीनों जगह पर पुलिस ने नीट के पेपर लीक प्रकरण में कई लोगों को गिरफ्तार किया। ये बातें उस समय चुनावी शोर में दब गई थीं। लेकिन पूरा एक कुचक्र जो मेधावी छात्रों का भविष्य का बैट्टा पार कर रहा था उस पर किसी का ध्यान नहीं था।

BRIEF NEWS

विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र का पद से इस्तीफा

PATNA : बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने पद से त्यागपत्र दे दिया है। वे 25 अगस्त, 2022 को बिहार विधान परिषद के सभापति चुने गये थे। इससे पूर्व वे तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से सन 2002 में निर्दलीय एवं 2008 में जनता दल (यू.) से बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। सन 2008 में बिहार सरकार में आनंद प्रबंधन विभाग के मंत्री रहे। सन 2014 में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय सदस्य के रूप में तथा 2020 में जनता दल (यू.) से तिरहुत स्नातक क्षेत्र से बिहार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए।

नवादा के डीएम आशुतोष ने दूसरी बार संभाला पदभार

NAWADA : नवादा के डीएम के रूप में शुक्रवार को दूसरी बार आशुतोष कुमार वर्मा ने पदभार संभाला। वे वर्तमान जिलाधिकारी प्रशांत कुमार से पदभार ग्रहण किया है। लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग के आदेश पर आशुतोष कुमार वर्मा को चुनाव कार्य से अलग किया गया था। जिसके बाद आयोग के निर्देश पर प्रशांत कुमार को नवादा का जिलाधिकारी बनाया गया था। चुनाव संपन्न होने के बाद बिहार सरकार ने आशुतोष कुमार वर्मा को नवादा के जिलाधिकारी के रूप में दूसरी बार पदस्थापित किया है।

60 ग्राम हेरोइन के साथ दो युवक गिरफ्तार

ARARIYA : भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ड्रग्स की तस्करी हो रही है। अररिया से सटे विभिन्न इलाकों में ब्राउन शुगर और हेरोइन जैसे नशीले पदार्थों की लगातार बरामदगी इस बात की स्पष्ट भी करता है। ताजा मामला नेपाल के मोरंग जिला अंतर्गत सुनवर्षी नगरपालिका वार्ड संख्या-09 स्थित डाईनिया बाजार का है। जहां बोलबम पेट्रोल पम्प के समीप हेरोइन के साथ दो कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नशे के सौदागरों में एक भारतीय और एक नेपाली नागरिक है। गिरफ्तार युवक की पहचान अररिया जिले के पोखरिया पंचायत वार्ड संख्या तीन निवासी राजकुमार राजा के 19 वर्षीय पुत्र राहुल राजा और नेपाल सुनवर्षी के डाईनिया निवासी प्रदुमन कुमार दास के 24 वर्षीय पुत्र आदर्श दास के रूप में की गई है।

दिनदहाड़े किसान के घर साढ़े तीन लाख की चोरी

ARARIYA : फारबिसगंज थाना क्षेत्र के मटियारी पंचायत के भद्राबाड़ी देव टोला में शुक्रवार के दोपहर किसान धीरेंद्र देव के बंद घर में अज्ञात चोरों ने साढ़े तीन लाख रुपए मूल्य की परिसंपत्तियों की चोरी कर ली। चोरों ने घर के दरवाजे पर लगा ताला को तोड़कर घर में प्रवेश कर घर में लकड़ी के अलमारी, ट्रंक और गोदरेज को तोड़कर उसमें आकर के नगद समेत साढ़े तीन लाख रुपए मूल्य की परिसंपत्तियों की चोरी कर ली। घटना के संदर्भ में पीड़ित किसान धीरेंद्र देव पिता रम. ब्रज बिहारी देव ने बताया कि बखाल में ससुराल में मौत के एक साल बाद होने वाले बरसी के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए परिवार के सभी सदस्यों के साथ गया हुआ था।

बेगूसराय के नवनीत सिंह ने नौकरी छोड़कर खड़ा कर दी कंपनी, आज 500 करोड़ का है टर्नओवर

सपने को लगे पंख, हासिल हुआ मुकाम

AGENCY BEGUSARAI :

सपने उन्हीं के सच होते हैं जो मुश्किलों से नहीं घबराते हैं और मुश्किलों का डटकर सामना करते हैं। जो व्यक्ति अपने हालात और परिस्थिति की चिंता किए बिना संघर्ष करता है वही सफलता की मुकाम तक पहुंचता है। बिहार के रहने वाले नवनीत सिंह इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। जिन्होंने एक छोटे से गांव से निकलकर 500 करोड़ का टर्नओवर कर सफलता की कहानी लिखी है।

बता दें कि नौकरी पाने वालों और नौकरी देने वालों के बीच की दूरी को कम करने के लिए उन्होंने एक एचआर ब्रांड की शुरुआत की है। यह कंपनी स्टॉफिंग, हायरिंग, सेल्स एंडउटसॉर्सिंग, अस्थायी स्टॉफिंग, टैलेन्ट एक्ज्यूजिशन, वॉल्यूम हायरिंग और

बुधौली स्कूल के पास अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम, जांच में जुटी पुलिस

नवादा में मुखिया की गोली मारकर हत्या, मचा कोहराम

AGENCY NAWADA :

नवादा जिले के पकरीबरावां प्रखंड के बुधौली पंचायत की मुखिया पप्पू मांडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पंचायत में चल रहे राजनीतिक विजह से हत्या के आसार लग रहे हैं। गुरुवार की देर रात घटना को अंजाम दिया गया। शुक्रवार को गांव में ही स्थित इंटर विद्यालय के समीप चहारदिवारी से सटे मुखिया का शव पाया गया। गोली मारकर हत्या की गई है। शव को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था नजदीक से कनपटी में गोली मारी गई। सूचना के बाद डीएसपी पकरीबरावां महेश कुमार चौधरी और पकरीबरावां थाना की पुलिस घटना

● मुखिया संघ के अध्यक्ष ने की इस मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग



मृतक बुधौली पंचायत के मुखिया पप्पू मांडी।

स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। प्राथमिक जांच में हत्या

● पप्पू मांडी के सर में मारी गई है गोली, इलाके में दहशत का माहौल



के पीछे राजनीतिक पाया गया उससे हत्या के पीछे कुछ और कहानी भी हो

जल्द होगी गिरफ्तारी

मिली जानकारी के अनुसार बदमाशों ने मुखिया की गोली मारकर हत्या करके आराम से फरार हो गए। मुखिया की गोली मारकर हत्या के मामले में डीएसपी के साथ तमाम पुलिस पदाधिकारी गांव में कैप कर रहे हैं। वहीं, डीएसपी महेश चौधरी ने कहा कि मुखिया की गोली मारकर हत्या की गई है। फिलहाल पूरे मामले की हर एक बिंदु पर जांच की जा रही है। जल्द ही अपराधी की खोजबीन कर पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

सकती है। घटनास्थल पर मुखिया का फैंट शर्ट लाश के नीचे रखा था।

रूपौली से कलाधर मंडल होंगे जदयू के उम्मीदवार



गौडिया को जानकारी देते जदयू के पदाधिकारी।

AGENCY PATNA :

बिहार में रूपौली विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव 10 जुलाई को होगा। इसको लेकर शुक्रवार को जनता दल यूनाइटेड (जदयू) और राजद ने अपने-अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने जदयू पार्टी कार्यालय में ऐलान किया कि पार्टी ने रूपौली विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव के लिए कलाधर मंडल को सिंबल दिया है। शिक्षक की नौकरी छोड़कर राजनीति में आये कलाधर मंडल 2020 के विधानसभा चुनाव में पहली बार निर्दलीय खड़े हुए थे और

उन्हें छह हजार से अधिक वोट मिले थे। वर्तमान में इनकी पत्नी मुखिया है। पिछले ही दिनों मंत्री लेशी सिंह ने कलाधर मंडल को सीएम नीतीश कुमार से भी मिलवाया था। इसके बाद अब इनके नाम पर फाइनल मुहर लग गयी है। दूसरी ओर, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने रूपौली उपचुनाव में अवधेश मंडल को उम्मीदवार बनाया है। वे 18 जून को नामांकन करेंगे। रूपौली उपचुनाव के लिए 14 से 21 जून तक नामांकन की तिथि है। 24 जून को स्कूटी और 26 जून को नाम वापसी की तिथि है।

नीतीश ने फिर दिल्ली में बुलाई जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक

PATNA : पटना नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अगली बैठक तब हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से नीतीश कुमार ने आगामी 29 जून को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। मीटिंग में जनता दल यूनाइटेड के सभी सांसद, विधायक और प्रमुख नेता शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में लोकसभा चुनाव के परिणाम से लेकर बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी समेत संगठन को विस्तार देने और मजबूत बनाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों जदयू के नेता आपस में मंथन करेंगे। इससे पहले 29 दिसम्बर 2023 को जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी जिसका देश की राजनीति पर व्यापक असर पड़ा। लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरीके के नतीजे सामने आए हैं उसमें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू किंग मेकर की भूमिका में उभरी है।

बालिका गृह कांड : सीबीआई के रडार पर मास्टरमाइंड ब्रजेश ठाकुर के कई करीबी

AGENCY MUZAFFARPUR :

बिहार के चर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को लेकर सीबीआई ने एक बार फिर शहर के कई लोगों को रडार पर लिया है। ब्रजेश ठाकुर और उसके एनजीओ सेवा संकल्प एवं विकास समिति से जुड़े करीबियों पर सीबीआई की नजर है। एनजीओ से जुड़े कई लोगों से मामले में सीबीआई पूछताछ कर सकती है। मामला बालिका गृह से हजारीबाग की किशोरी को रहस्यमय ढंग से गायब कर देने का है। बच्ची मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग थी। ऐसे में साजिश के तहत मानव अंग तस्करो के द्वारा बच्ची को गायब करने की आशंका है। इसमें ब्रजेश की एनजीओ और उसके कर्मियों की भी मिलीभगत की आशंका है। सीतामढ़ी सीडब्ल्यूसी के फर्जी रिलीज



ऑर्डर पर बालिका गृह से 10 नवंबर 2015 को हजारीबाग की बच्ची को गायब किया गया था। जिस दिन फर्जी रिलीज ऑर्डर जारी हुआ था, उसी दिन बच्ची को लेने उसके फर्जी माता-पिता बालिका गृह मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। फर्जी वोटर आई कार्ड बालिका गृह में दिया गया। माता-पिता की पहचान करने वाला हजारीबाग नयुनी मुखिया भी फर्जी था। सीबीआई को यह तथ्य बालिका

● कांड में 18 दिवियों को पहले ही सुनाई जा चुकी है सजा
● फरार बताई गई दो किशोरियों का भी अब तक नहीं मिला सुराग
● ब्रजेश ठाकुर समेत अन्य आरोपी तिहाड़ जेल में मौत होने तक आजीवन कारावास की काट रहे हैं सजा

किया गया था। रिलीज ऑर्डर असली था या नकली इस संबंध में किसी तरह की जांच बालिका गृह का संचालन कर रही एनजीओ के कर्मचारियों ने नहीं की थी। उसी दिन बच्ची को उनके फर्जी अभिभावकों को सौंप दिया गया था। नौ साल पहले गायब हुई दिव्यांग बच्ची का सीबीआई का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बालिका गृह कांड की जांच के दौरान में पता चला था कि गृह से 24 नवंबर 2013 को चार किशोरियां फरार हो गई थीं। लेकिन, ये बच्चियां कहाँ और कैसे गायब हुई इसकी जांच नहीं हुई थी। बालिका गृह कांड के खुलासे के बाद पुलिस ने 2018 में इसकी जांच की। पुलिस ने चार में दो का सुराग ढूँढा, लेकिन फुलपरास और नई दिल्ली के पहाड़गंज की दो किशोरी का कोई सुराग नहीं मिला।

जज के साथ साइबर फ्रॉड: नवगछिया सीजेएम को झांसा देकर साइबर फ्रिग्मिनल ने टग लिये आठ लाख

AGENCY NAUGACHIA :

बिहार में साइबर अपराधियों ने आतंक मचा रखा है। साइबर फ्रॉड आम आदमी से लेकर वीआईपी को निशाना बनाने से भी नहीं चूकते। भागलपुर के नवगछिया से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। साइबर अपराधियों ने नवगछिया के एसीजेएम 2 क ठगी का शिकार बना लिया। बदमाशों ने उनके खाते से 8 लाख 49000 रुपए उड़ा दिए। नवगछिया साइबर थाने में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। घटना की जानकारी मिलने पर लोग सन्न हैं। मामला नवगछिया के एसीजेएम 2 महेश्वर नाथ प्रसाद से जुड़ा हुआ है। जज साहब ने मामले की शिकायत नवगछिया साइबर थाने से की। इसके बाद कांड संख्या 8/2024 दिनांक 12.6.2024 दर्ज किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के योने एप



डाउनलोड करने के नाम पर यह फ्रॉडवाड़ा किया गया। पुलिस को दिए आवेदन में जूडिशल मजिस्ट्रेट महेंद्र नाथ पांडे ने बताया है कि उनका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सासाराम आदमपुर शाखा में है जहां से उन्होंने कर लोन लिया था। 11 जून को उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें ब्रांच मैनेजर से संपर्क करने को कहा गया था जब उन्होंने उसे नंबर पर कॉल बैंक किया तो दूसरी तरफ साइबर फ्रॉड थे लेकिन उन्होंने बैंक मैनेजर के नाम पर जज साहब को झंझसे में ले लिया। फ्रॉड ने उन्हें स्टेट बैंक का योने लाइट एप्लीकेशन डाउनलोड

नवादा में 10 साइबर अपराधी गिरफ्तार

साइबर थाने की पुलिस ने 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से 33 मोबाइल, 3 लैपटॉप, 50 एटीएम कार्ड, 40 पासबुक, 25 चेक बुक, 80 सिम कार्ड, एवं 95 हजार रुपये कैश सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि फ्रिग्मिनल के नाम पर साइबर अपराधी भोले भाले लोगों को टगने का काम करते थे। एसीपी कार्तिकेय के शर्म ने बताया कि ईओपी ने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी से डिजिटल में पर्सल पर डिस्कॉन्ट देने का झांसा देकर साइबर अपराधियों की ठगी की सुनना दी थी। साइबर थाने की डीएसपी रहं थानाध्यक्ष प्रिया ज्योति के नेतृत्व में एक एएसआईटी का पटन फंजीवड़ा किया गया। एएसआईटी ने विभिन्न जगहों पर ताबडोड़ छापेमारी कर दस साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। नवादा जिले के



नरहट थाना क्षेत्र के पतल बिगहा गांव के रम। रामशील सिंह के बेटे दीपक कुमार (26), पकड़िया गांव के शैलेंद्र सिंह के बेटे राजू रजन (27), कुमी गांव के रामसगर सिंह के बेटे अंकुश राज उर्फ आदित्य राज (26), नेगुरा गांव के धनंजय कुमार के बेटे रविरेज कुमार उर्फ अंकित कुमार (21), पकड़िया गांव के शैलेंद्र सिंह के बेटे निशांत कुमार उर्फ (24), मिलानी गांव के विजय प्रसाद के बेटे अशोक कुमार

करने के लिए कहा। इसी क्रम में साइबर फ्रॉड ने उनसे आवश्यक जानकारी ले ली और जज साहब

के खाते से 8 लाख 49000 उड़ा दिए। इस घटना की खबर सामने आने के बाद आम आदमी हैरान

हैं तो पुलिस विभाग परेशान कि जज साहब को साइबर फ्रॉड ने कैसे उग लिया।

सनकी पति ने कैची घोंप कर पत्नी को मार डाला

AGENCY SITAMARHI :

बिहार के सीतामढ़ी में पति-पत्नी के बीच विवाद ने ऐसा खूनी रूप अख्तियार किया कि दोनों की जान चली गई। सनकी पति ने पहले पत्नी की हत्या कर दी और जैसे ही उसे अपनी करतूत का एहसास हुआ की खुद को भी इस कदर जखमी किया कि अस्पताल ले जाने के रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना से इलाके के लोग सदमे में हैं। यह दुःखद घटना सीतामढ़ी के बोखरा थाना क्षेत्र के गढ़वाल गांव वार्ड संख्या 6 की बताई जाती है मृत पत्नी की पहचान बबोता देवी, 40 वर्ष जबकि पति की पहचान मैनेजर राय 42 वर्ष के रूप में हुई है। मैनेजर राय की बबोता से दूसरी शादी हुई थी। पुलिस मामले की खानबीन में जुट गई है। दोनों के शवों को आरंभिक जांच के बाद पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी



सदर अस्पताल भेज दिया गया है। गांव के लोग इस घटना से इस कदर सदमे में हैं कि कोई कुछ बोल नहीं रहा है। चारों ओर सन्नाटा पसरा है। पुलिस की जीप बीच-बीच में थरती करने आ जाती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना गुरुवार देर रात की है। पति-पत्नी के बीच पहले से कहा सुनी होती थी। गुरुवार की रात मामला बहुत बढ़ गया। गुस्से में आकर मैनेजर राय ने कैची उठाकर पत्नी पर हमला कर दिया। कैची से उसने पत्नी को कई स्थानों पर बुरी तरीके से गोद दिया जिससे घटनास्थल पर ही बबोता देवी की मौत हो गई।

जीतन राम मांडी का राजद पर बड़ा हमला, बोले-

अपराध के मुद्दे पर केवल थैथरई करते हैं तेजस्वी

AGENCY GAYA :

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांडी ने राजद पर बड़ा हमला किया है। बिहार में बढ़ते अपराध पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोप का करारा जवाब देते हुए जीतनराम मांडी ने कहा कि तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव थैथरई करते हैं, उनको पहले सही से मामले की जानकारी रखनी चाहिए, तब बोलना चाहिए। जीतन राम मांडी ने कहा कि लालू परिवार को लॉ एंड ऑर्डर पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है। चाहे तेजस्वी यादव हो या लालू यादव हो, इन दोनों को अपराध पर बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखें पहले अपना पुराना इतिहास संख्या चाहिए। उसके बाद कुछ भी बोलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री मांडी ने कहा कि



वर्तमान में यदि अपराध की संख्या बढ़ी है, तो उसे पर कार्रवाई हो रही है और तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। उनके समय में एक्शन तो दूर की बात है उल्टा अपराधी उनके घर जाते थे और चाय पीकर वहां नेगोशिएशन किया जाता था। लेकिन, अब ताकत नहीं है कि कोई ऐसा करे। मांडी ने तेजस्वी को सलाह देते हुए कहा कि वह जो कुछ भी कह रहे हैं वह सही नहीं कह रहे हैं।

प्रशिक्षु दारोगा को तेज रफ्तार पिकअप ने रौंदा

BIHARSARIF : तेज रफ्तार पिकअप ने वाहन चेंकिंग के दौरान प्रशिक्षु दारोगा को रौंदा डाला है। दारोगा का पटना में इलाज चल रहा है। उसकी हालत गंभीर बतायी जा रही है। प्रशिक्षु दारोगा रविचंजन उर्फ गौतम शेखपुरा-बरबोधा बिहार श्रीफ रोड पर गुरुवार की रात वाहन जांच कर रहा था। इसी दौरान प्रशिक्षु दारोगा रविचंजन उर्फ गौतम को तेज रफ्तार पिकअप ने रौंदा दिया। दारोगा शेखपुरा जिले के मिशन थाना में तैनात था। घटना महावीर चौक और मिशन थाना के बीच में घटित हुई है। वायल अवस्था में दारोगा को बरबोधा फेररल अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिर में गंभीर चोट होने और अन्य जगहों पर भी चोट होने की वजह से प्राथमिक उपचार के बाद दारोगा को रेफर कर दिया गया। उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है।

विश्व रक्तदाता दिवस पर केएम हॉस्पिटल हुआ 135 यूनिट ब्लड संग्रह

केएम में हर साल की भांति इस बार भी हुआ रक्तदान, बढ़चढ़ कर स्टाफ ने लिया हिस्सा

मथुरा। केएम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 14 जून (शुक्रवार) रक्तदाता दिवस को लेकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष एवं केएम विवि के कुलाधिपति किशन चौधरी ने किया। इस मौके पर विवि एवं हॉस्पिटल के अधिकारी कर्मचारियों ने रक्तदान किया। शिविर में कुल 135 यूनिट ब्लड संग्रह हुआ। इस मौके पर श्री चौधरी ने कहा कि रक्तदान महादान है, लोगों को अपने जीवन में रक्तदान जरूर करना चाहिए। इससे आप किसी के जीवन को बचा सकते हैं, कहा कि पिछले साल भी केएम में रक्तदान शिविर



का आयोजन हुआ था और इस बार भी पूरे स्टाफ ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया है, ब्लड डोनेट करने वालों को प्री हैलमेट दिया गया है। केएम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रक्तदाता दिवस को लेकर आज रक्तदान शिविर लगाया गया।

जिसका शुभारंभ सुबह 9 बजे से शुरू हुआ जो 5 बजे तक चला। शिविर का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष एवं केएम विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के चेयरमैन किशन चौधरी ने किया। सबसे पहला



रक्तदान फरह कश्यप के युगडाई के ग्राम प्रधान प्रताप सिंह ने करते हुए दूसरों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। इस दौरान रक्तदान करने वाले डोनों को केएम विवि के कुलाधिपति श्रीचौधरी ने निःशुल्क हैलमेट तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। केएम मेडिकल

कालेज एंड हॉस्पिटल के एडिशनल मेडिकल सुपरिटेण्डेंट डा. आरपी गुप्ता ने कहा कि साल में कम से कम तीन से चार बार रक्तदान कर सकता है। अगर स्वैच्छिक रूप से लोग रक्तदान के लिए आगे आएंगे तो ब्लड बैंक में खून की कमी नहीं होगी। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है।

संक्षिप्त डायरी

लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड मथुरा में टला बड़ा हादसा

स्टेनो रुम के से सटे बिजली के बड़े बॉक्स में लगी आग

मथुरा। तीन दिन पहले मथुरा के लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड में बिजली के बड़े बॉक्स में आग लग गई। जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। जहां आग लगी उसी से सटा हुआ स्टेनो का रुम है। जिसमें आग की लपटें अंदर तक चली गईं कार्यालय में अफरातफरी मच गई। आग की चपेट में आने से स्टेनो बाल बाल बचीं। बिजली मुश्किल से कर्मचारियों ने स्टेनो को बाहर निकाला। मजे की बात तो यह कि उस समय ऑफिस में अधिशासी अभियंता से लेकर अधिनस्थ अधिकारी मौजूद थे। इंसायिबत की परकाष्ठा देखिए कि अधिशासी अभियंता ऑफिस में ऐसी में बैठकर मटर गस्ती करते रहे मगर बाहर निकल कर देखने की जहमत नहीं उठाई। घटना के बाद भी आलाधिकारियों ने सबक नहीं लिया। और स्टेनो उसी रुम में बैठकर कार्य कर रही हैं। उनका कमरा तक नहीं बदला गया है। ऐसा लगता है कि अधिशासी अभियंता किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं।

रजिस्ट्री ऑफिस के सामने दस्तावेज लेखकों ने दिया धरना

मथुरा। रजिस्ट्री कार्यालय में काम की परिस्थितियों से असंतुष्ट दस्तावेज लेखकों ने परिस्थितियों में सुधार की मांग की है। रजिस्ट्री ऑफिस में बैनामा पंजीकृत करने वाली ऑनलाइन साइट सुचारु रूप से न चलने के कारण आज समस्त दस्तावेज लेखकों ने कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर कार्य स्थिति को सुधारने की उपनिबंधक से मांग की। इससे पहले दस्तावेज लेखक निबंधन समिति के पदाधिकारियों ने उप निबंधक को ज्ञापन सौंप कर साइट को ठीक करने की मांग की थी। आज सुबह रजिस्ट्री कार्यालय के सामने सुभाष चतुर्वेदी, संतोष कुमार गौतम, सोहनलाल शर्मा, एड महेंद्र निरंजन सिंह, बिल्लू सिंह, महावीर सिंह, ज्ञान प्रकाश एड, दिनेश कुमार, गजेंद्र पाल सिंह, विक्रम सिंह, हरीश शर्मा, पीएस पाठक, अनिता चावला सहित एक दर्जन से ज्यादा दस्तावेज लेखकों ने कार्यालय के बाहर धरना देकर बैनामा पंजीकृत करने वाली ऑनलाइन साइट को ठीक करने की मांग की है।

कारखाने में काम कर रहे थे मजदूर तभी फट गया सिलेंडर

मथुरा। गोविंद नगर क्षेत्र में एक कारखाने में गैस सिलेण्डर फटने से चार मजदूर बुरी तरह झुलस गये। गैस सिलेंडर में लगी आग की चपेट में आने से चार लोग झुलसे हैं जिनमें से दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। थाना गोविंदनगर क्षेत्र के अंतर्गत चौक बाजार स्थित कटरा बाजार में कारखाने में गैस सिलेंडर में पहले आग लगी। इसके बाद तेज धमाके की आवाज के साथ सिलेंडर फट गया। मौके पर काम कर रहे चार मजदूर इसकी चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गये। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने झुलसे लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने झुलसे हुए दो लोगों की गंभीर गलत बताते हुए रेफर करने की बात कही। वहां मौजूद लोगों से जानकारी प्राप्त कर पुलिस ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

बिना टिकट/अनाधिकृत यात्रा करने वालों के विरुद्ध चलाया गया विशेष चेकिंग अभियान

मथुरा। मंडल रेल प्रबंधक आगरा तेज प्रकाश अग्रवाल के निर्देशानुसार व वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आगरा अमित आनन्द के निर्देशन मे रेल सुरक्षा बल के साथ बिना टिकट यात्रियों की रोकथाम हेतु दिनांक-14.06.2024 को गोवर्धन स्टेशन पर और ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा, अनियमित यात्रा, बिना बुक लगेज, गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध किलाबंदी जांच की गई। जांच के दौरान 146 बिना टिकट यात्रियों से रु-57,930/-, अनाधिकृत यात्रा करने वाले 45 यात्रियों से रु- 18,380/- तथा गंदगी फैलाने वाले 08 यात्रियों से रु-900/- सहित कुल 199 यात्रियों से रु- 77,210/- का जुमाना वसूल किया गया। गोवर्धन स्टेशन पर जांच में भूलेश पांडे डीसीआई, दीपक गुप्ता डीसीआई, एल आर मीना डीसीटीआई, रघुवर दयाल सीटीआई व अन्य टिकट जांच कर्मचारी मौजूद रहे। जनसंपर्क अधिकारी कु. प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि इस प्रकार की जांच मंडल में निरंतर कराई जा रही है। अतः यात्रियों से अनुरोध है कि वह उचित यात्रा टिकट लेकर एवम निर्धारित सीमा से अधिक सामान को बुक कराकर ही यात्रा करे तथा रेल परिसर में गंदगी न फैलाए।

गरीब मेधावी छात्रों को मददगार बनेगी विद्याधन छात्रवृत्ति

मथुरा। विद्याधन द्वारा प्रदान की जाने वाली अखिल भारतीय उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में गरीब परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए मददगार होगी। इसके लिए पात्र छात्र-छात्राओं से 15 जुलाई तक आवेदन मांगे गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक भास्कर मिश्रा ने बताया कि विद्याधन एक अखिल भारतीय उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति है। जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी छात्रों के लिए है। इस योजना के अंतर्गत छात्र-छात्राओं को इंटरमीडिएट में प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। जबकि डिग्री कोर्स करने के लिए 15 हजार से 75 हजार रुपये के बीच छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्र सीधे विद्याधन को वेबसाइट पर सीधे निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम हो, जिन छात्रों ने 2024 में 10 वीं की परीक्षा 80 प्रतिशत अंकों से अधिक व 8 सीजीपी अं, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 65 प्रतिशत अंक या 6.5 सीजीपी अंक के साथ उत्तीर्ण की हो। आवेदन के साथ कक्षा 10 का अंकपत्र एवं आय प्रमाणपत्र लगाना आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए हेल्प डेस्क नं. 9663517131 एवं वाट्सएप नं. 8296010803 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

कुल्लड़ के दूध की जगह अंडों की ढकेलों और मोमोज के खोमचों ने ले ली

मथुरा। कुल्लड़ का दूध और दूध की कढ़ाई लगाने वाली हलवाई की दुकानें गिनी चुनी रह गयी हैं। मथुरा के पुराने शहर क्या लगभग यूपी के सभी शहरों के पुराने बाजारों में हर 200-300 मीटर पर दूध की कढ़ाई वाली हलवाई की दुकान हुआ करती थी। आज हर 500 मीटर पर दारू की दुकान तो मिल जाएगी 200 मीटर पर अंडा और मोमोज मिल जाएंगे 100 मीटर में दर्जनों धीमे जहर की लड्डियों से सजी दुकानें मिल जाएंगी जिन्हें शान से लोग गुटखा कहते हैं। और खाकर सार्वजनिक संपत्ति को पीक मारकर



नुकसान करते हैं। लेकिन कढ़ाई का कुल्लड़ वाला दूध गिनी चुनी दुकान पर ही रह गया है। मोटी मलाई वाला दूध और मिट्टी के कुल्लड़ में अब केवल ब्याह शदी में ही देखने को मिलता है लेकिन उसमें भी दूध की वह गुणवत्ता नहीं

होती जो पहले दुकानों पर हुआ करती थी। वह स्वाद ही नहीं है न ही उतने समय तक मंदा मंदा आंच पर उस दूध को अंधोत्र किया गया होता है। खाने खिलाने के शौकीन हवा हवाई हो गए दूध पीएंगे तो बिना चीनी का रोटी खाएंगे तो बिना चुपड़ी। हर खेत मे रोग बोया गया हर घर मे फास्ट फूड भरा पड़ा है लोग कहते है इन चीजों को खाने से गरमाई आती है शरीर बनता है बिल्कुल बनता होगा लेकिन अक्ल ठसस हो जाती है। अक्ल भी तेज हो और गरमाई भी आये तो केसर पिस्ता का दूध पीजिये। पिच्चा, बर्गर चाउमीन अगर नहीं खिलाये तो बच्चों से पहले उनकी मम्मी नाराज हो जाएंगी अब क्या करे एक बाव्य जो तेजी से घूमता है बच्चे आजकल हमारी सुनते ही नहीं हैं। समाज परिवर्तन की जो बनावटी परिभाषा आज हमने गढ़ी है न वह हमारी संस्कृति से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती और किराये की चीज वह लेते हैं। जिनके पास अपनी नहीं होती।

जब साइकिल लोगों की शान हुआ करती थी

पर्यावरण के लिए भी यह नुकसानदायक नहीं

मथुरा। एक वो भी जमाना था जब साइकिल लोगों की शान हुआ करती थी जब दहेज में भी साइकिल दी जाती थी वैसे साइकिल के भी अपने बहुत फायदे हैं यह स्वस्थ रखती है! लेकिन अब चारों ओर गाड़ियों के शोर और दिखावे के बावजूद आज भी हमारे लिए साइकिल की उपयोगिता कम नहीं हुई है! कोरोना काल के दौरान और उसके बाद भी साइकिल की विक्री बाजार में बढ़ी है साइकिल चलाना हर तरफ से लाभदायक है इससे शारीरिक सेहत बरकरार रहती है प्रतिदिन साइकिल चलाने से व्यक्ति का शक्कर का स्तर और रक्तचाप सामान्य रहता है। सच यह है कि साइकिल चलाना एक संपूर्ण व्यायाम है पर्यावरण के लिए भी यह नुकसानदायक नहीं है क्योंकि अन्य वाहनों की तरह इससे धुआं नहीं निकलता है और वायु प्रदूषण नहीं होता है कई देशों के लोग सबसे ज्यादा साइकिल चलाने हैं साइकिल लोगों के खर्च को भी कम करते हैं



हमारे देश सहित संपूर्ण विश्व में साइकिल संस्कृति को बढ़ावा मिलना चाहिए जिससे बढ़ते प्रदूषण

से है राहत मिल सके क्यों ना सरकार को हफ्ते में एक दिन के लिए फोर व्हीलर व टू व्हीलर

आयुष्मान के अधिक से अधिक कार्ड बनाने पर जोर

मथुरा। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग बैठक संपन्न हुई। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अजय कुमार वर्मा को निर्देश दिये कि मरीजों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएं। जिले के समस्त स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें। अस्पतालों में आने वाले मरीजों एवं उनके साथ आने वाले तीमारदारों के बैठने, पंखे, पेयजल एवं प्रसाधन के बेहतर से बेहतर प्रबंध किए जाएं। सीएमओ को निर्देशित किया गया की कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत अधिकाधिक परिवारों को लाभान्वित करें, कन्या के जन्म होते ही उनका रजिस्ट्रेशन कराएं। समस्त पीएचसी एवं उप केन्द्र स्तर पर स्थापित हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर को क्रियाशील कर अधिक से अधिक लोगों को ई-संजीवनी ओपीडी से आच्छादित किया जाए। आयुष्मान भव योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाने में प्रगति लाएं और सभी केंद्रों की निरंतर प्रगति का निरीक्षण करें। आयुष्मान कार्ड बनाने में आंगनबाड़ी केंद्रों, राशन की दुकानों के कोटेदारों, आशा आदि की मदद लेते हुए अधिकाधिक कार्ड बनवाएं। संचारी रोग नियंत्रण हेतु जिला पंचायत राज विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तम स्वच्छता हेतु निर्देशित किया गया। नगर निगम को शहरीय क्षेत्र में फॉगिंग, टेम्पोस छिड़काव, नियमित साफ सफाई आदि के निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीना, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अजय वर्मा, सी.एम.एस जिला चिकित्सालय तथा स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।



मथुरा के रहने वाले हरेंद्र चौधरी ने पत्रकारिता जगत में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है इन्हें पीटीआई (प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया) के Consulting Editor उत्तर प्रदेश नियुक्त किया गया है हरेंद्र चौधरी जी को इस नई जिम्मेदारी के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं

राधा रानी पर भिड़ने वाले कथावाचक और संत कैसे पहुंचे शोहरत के शिखर पर

मथुरा। उत्तर प्रदेश राधा के पति का नाम अनय घोष, उनकी सास का नाम जटिला और ननद का नाम कुटिला था। राधाजी का विवाह छता में हुआ था। राधाजी बरसाना की नहीं, रावल की रहने वाली थीं। बरसाना में तो राधाजी के पिता की कचहरी थी, जहां वह साल भर में एक बार आती थीं-पंडित प्रदीप मिश्रा, कथावाचक 4 श्लोक क्या पढ़ लिए, प्रवक्ता बन गए? तुझे नरक से कोई नहीं बचा सकता। हमें गाली दो तो चलेगा। लेकिन तुम हमारे इष्ट, हमारे गुरु, हमारे धर्म के खिलाफ बोलेंगे, उनका अपमान करोगे, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हें बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे। -प्रेमानंद महाराज, संत राधा रानी के जन्म और श्रीकृष्ण से उनके विवाह को लेकर देश के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप



मिश्रा और संत प्रेमनंद महाराज में विवाद शुरू हो गया है। एक शिव के भक्त हैं, दूसरे राधा रानी के। प्रदीप मिश्रा मध्यप्रदेश के सीहोर में रहते हैं, तो प्रेमनंद जी वृंदावन में। आइए, जानते हैं दोनों के बचपन से लेकर प्रसिद्ध कथावाचक और संत बनने की कहानी 13 साल की उम्र में प्रेमनंद जी महाराज ने घर छोड़ दिया था उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले का नरवल तहसील का अखरी गांव। ये जगह है, जहां प्रेमनंद महाराज का जन्म और पालन-पोषण हुआ। यहीं से निकलकर वो इस देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी में बस गए। उनके बड़े भाई गणेश दत्त पांडे बताते हैं- मेरे पिता शंभू नारायण पांडे और मां रामा देवी हैं। हम 3 भाई हैं, प्रेमनंद मझले हैं। वो बताते हैं कि प्रेमनंद हमेशा से प्रेमनंद महाराज नहीं थे।

घर छोड़ दिया बचपन में अनिरुद्ध ने अपनी सखा टोली के साथ शिव मंदिर के लिए एक चबूतरा बनाया। इसका निर्माण भी शुरू करवाया, लेकिन कुछ लोगों ने रोक दिया। इससे वह मायूस हो गए। उनका मन इस कदर टूटा कि घर छोड़ने का फैसला कर लिया। एक दिन देर रात खाना खाया और रोज की तरह छत पर बने कच्चे कमरे में जाकर सो गए। अगली सुबह जब बड़े भाई ने जगाने के लिए आवाज लगाई, कमरे से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने ऊपर जाकर देखा तो अनिरुद्ध कमरे में नहीं थे। खोजबीन शुरू की गई। काफी मशक्कत के बाद पता चला कि वो सरसौल में नंदेश्वर मंदिर पर रुके हैं। घरवालों ने उन्हें घर लाने का हर जतन किया, लेकिन अनिरुद्ध नहीं माने। फिर कुछ दिनों बाद बची-खुची मोह माया भी छोड़कर वह सरसौल से भी चले गए। नंदेश्वर से महराजपुर, कानपुर और फिर काशी पहुंचे आज जिन प्रेमनंद महाराज के भक्तों में आम आदमी से लेकर सेलिब्रिटी तक शुमार हैं, उनकी पढ़ाई-लिखाई सिर्फ 8वीं कक्षा तक हुई है। 9वीं में भास्करानंद विद्यालय में एडमिशन दिलाया गया था, लेकिन 4 महीने में ही स्कूल छोड़ दिया। इसके बाद बड़े भगवान की भक्ति में लीन हो गए। सरसौल नंदेश्वर मंदिर से जाने के बाद वह महराजपुर के सैमसी स्थित एक मंदिर में कुछ दिन रुके। फिर कानपुर की बड़ौदा में रहे। इस तरह से धीरे-धीरे उनकी रूचि अध्यात्म की ओर बढ़ने लगी। जब 13 साल के हुए तो उन्होंने ब्रह्मचारी बनने का फैसला किया। इसके बाद घर का त्याग कर संन्यासी बन गए।

Time to put S&T policies back on track

IN the past 10 years, innovation was perhaps the most quoted buzzword in speeches of the Prime Minister, Cabinet ministers and science bureaucrats in India. Several awards, missions and schemes were announced to promote science-based innovation in different sectors. It is, however, surprising that all this was happening without a proper enabling environment. The grand intentions of the Modi 2.0 government to boost scientific research remained a 'work in progress' at a time when the global research landscape is fast changing with the emergence of deep tech. Little progress was made on three critical counts — science and technology (S&T) policies, funding mechanisms and research priorities — and the new government's agenda should be to prioritise them. An exercise to develop a new National Science, Technology and Innovation (STI) policy was initiated during the Covid-19 pandemic in 2020. Several drafts were prepared, but the policy remains on paper and is yet to be finalised. The policy was to replace the one released in 2013 by the UPA government. The first task of the new government on the science and technology front, therefore, should be to finalise the STI Policy and start its implementation in earnest. If the new dispensation finds that the draft is not good enough, it should junk it and continue with the 2013 STI policy framework. The policy goals enunciated in 2013 remain unfulfilled even after a decade. Among the key objectives of the 2013 policy was to 'position India among the top five global scientific powers by 2020' and to increase the gross expenditure on R&D (GERD) to 2 per cent of the GDP. We have seen little progress on the expenditure front. India has slipped on this parameter. The GERD in 2013 was 1 per cent of the GDP. It came down to 0.66 per cent and 0.64 per cent during 2019-20 and 2020-21, respectively, according to the latest available data from the Department of Science and Technology. The 2013 policy was unequivocal about the need to increase GERD and enhance public investment in scientific research, but the 2020 STI draft is vague on this count. It talks of developing a 'financial landscape of the STI ecosystem' in which departments and ministries of the central, state, and local governments as well as government and private companies will set up an STI unit with 'a minimum earmarked budget to pursue STI activities.' On the face of it, it is an outdated idea. It was first proposed in the 1980s. The technology development roadmap suggested in the draft is equally adrift. The policy draft seeks to promote technology self-reliance and indigenisation to achieve the larger goal of Atmanirbhar Bharat. For this, a two-way approach has been prescribed — indigenous development of technology as well as technology indigenisation. At the same time, it says, "international engagements will be facilitated to gain essential know-how towards creation and development of indigenous technologies."

Another grand idea of the Modi government was the National Research Foundation (NRF) as a supra-research funding agency. It was first announced by Finance Minister Nirmala Sitharaman in her Budget speech in 2019. The NRF is still to see the light of day even after Parliament passed a Bill for its formation in 2023. The idea of a funding agency along the lines of America's National Science Foundation was first proposed by the Scientific Advisory Committee to the Prime Minister, headed by Prof CNR Rao, in 2005. As a result, the Science and Engineering Research Board (SERB) was established in 2008 to streamline funding for scientific research. The NRF Act of 2023 repealed the SERB Act of 2008 and dissolved SERB. There has been no credible justification from the government for replacing SERB with a new body. The only intention seems to be to create a centralised body to fund and also regulate research. NRF's Governing Board will be presided over by the Prime Minister and two ministers (Science and technology and education) will be the Vice-Presidents. Even with SERB, researchers complained of bureaucratic delays, one can imagine the fate of such a heavily political governing structure for the NRF. In a large and diverse country like India, do we need a centralised funding mechanism based in New Delhi or multiple channels of funding in different sectors?

Focus on agriculture as the fulcrum of economic growth

The need of the hour is to promote precision farming, which can give us more from less.

THE new government is expected to spell out a fresh policy to boost economic growth and improve consumption as well as investment. In the past decade, absolute power enabled the BJP-led government to formulate and push policies of its choosing swiftly without any concern over political opposition. Now, it is a different ballgame. The emphasis will be more on compromise and accommodation.

The chances are that economic growth will slow down a bit. Hence, the challenge will be to devise innovative ways to arrest the slide. It is hoped that technology will help turn the tide. The government should focus particularly on agriculture. Modi 3.0 has made a good start on this front by releasing the PM Kisan Nidhi instalment of Rs 20,000 crore to transfer Rs 6,000 each per year into the bank accounts of over nine crore farmers. But there has to be a follow-up after the sop. There has to be a new technology policy to take agriculture forward. The government can take a cue from the success story which Madhya Pradesh crafted to transform agriculture. Perhaps fittingly, former CM Shivraj Singh Chouhan, who did a good job in his home state, will hopefully do it at the Centre too as the new Union Agriculture and Rural Development Minister.

During the 10-year period till 2022-23, agriculture grew in MP by 6.1 per cent on an average annually compared to the national average of 3.9 per cent. One way in which this was done was not by putting under the plough virgin land but by more cropping. By cropping on the same land, the net sown area went up multiple times.

Other than effectively having more land, Madhya Pradesh was able to get more water. It did not build new canals but instead had concrete lining done for existing ones, besides desilting, cleaning and fixing breaches. Thus, the state was able to get a lot of canal areas without having to dig in entirely new ones. There should not necessarily be any effort by the Centre to get the states to go in for all this. There may be discord between states over groundwater drawn by irrigation tubewells that run on subsidised power. The Centre needs to persuade the states to move away from this process so that the sharp drop in groundwater levels can be curbed.

The government also needs to spur agriculture by bringing in new technology. The use of fertilisers, which helped usher in the Green Revolution, is becoming passe. New technology is needed to protect crops from pests, pathogens and weeds. Mechanisation and agronomic intervention can be promoted. Tractors have practically replaced bullocks. Now, there are new ploughs that can do deep tillage, mix pulverised soil and break hardpan layers. There is also new technology for irrigation -- drip irrigation and laser land levellers which place seeds and fertilisers. What can be done can be visualised from the



fact there are pomegranates being grown in Rajasthan on arid land through drip irrigation and water-soluble liquid fertilisers. When it comes to the new technologies for which the Centre is seeking support from the states, there is an overriding concern. The country needs to preserve land, water and air so that its citizens, who now number the largest in the world, are able to grow enough to preserve themselves. They also need to be able to cope with heat and pollution. The new policies which have to be evolved must make the Centre and the states put their heads together so that biodiversity is preserved. The ever-growing number of people must be able to survive and thrive in a sustainable manner.

But the good news from academics is that if farmers follow the right practices, yields can return to normal levels after some time. What is needed are policy decisions with better and more scientific evidence instead of going back to nature as Sri Lanka attempted to do by trying to do away with fertilisers and Sikkim ventured to do as well.

The need of the hour is to promote precision farming, which can give us more from less. Geographical information system, artificial intelligence and machine learning, which can use enormous data to bring about

precision in farming, the use of sensors, drones, LEOs (low earth orbits), space technologies and cloud computing are all bursting out to provide the basis for a revolutionary epoch. Drips, hydroponics and aeroponics are available to get much more with very little exploitation of the planet's natural resources.

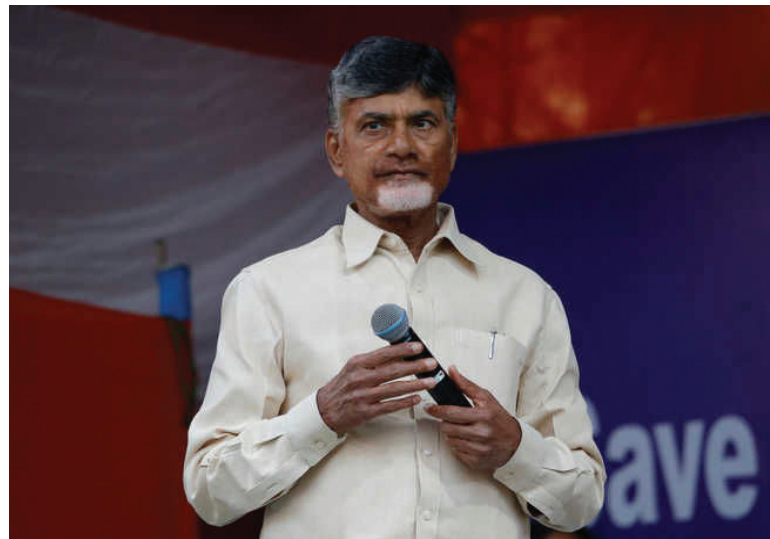
But what stands in the way of this is the political economy. Huge amounts of subsidy have been handed out by way of free power, free water and urea with 80-90 per cent subsidy. The subsidies may have been good in the 1960s and 1970s to meet the country's food deficit, but this has been continuing. Farmers in the northwestern region are continuing to grow the same paddy, wheat and sugarcane with state subsidy. The initiative by the government to enact new farming laws was negated by a long, revolutionary agitation. There is now an absolute need to ensure limited use of natural resources. The irrational exploitation of nature's wealth must be severely curtailed, if not stopped eventually. This is what the new government must try to do. To be able to do this, the Centre will need to have a dialogue and reach an agreement with the states. These are the new dynamics which the election outcome has handed down.

Two good for Naidu

Andhra CM a key stakeholder in Modi govt

IT's a 'best of both worlds' situation for Chandrababu Naidu. The Telugu Desam Party (TDP) supremo has not only become the Chief Minister of Andhra Pradesh for the fourth time, he has also emerged as a key stakeholder in the BJP-led government at the Centre. On Wednesday, he took oath as CM in the presence of Prime Minister Narendra Modi and other senior BJP leaders. The alliance comprising the TDP, the BJP and the Janasena Party recorded a landslide victory in the simultaneous Lok Sabha and Assembly elections in the southern state recently, winning 21 of the 25 Lok Sabha seats and 164 of the 175 Assembly seats. Notably, the TDP alone has the majority in the Andhra House with 135 MLAs.

Naidu's enviable status in the scheme of things has led to speculation that he might press Modi to walk the talk on granting special category status (SCS) to AP. The Congress has already



upped the ante against the PM, saying that he has failed to

fulfil the promise made in this regard in Tirupati in March 2014. The basis of Andhra's demand for SCS is the loss of revenue attributed to the state's bifurcation, which led to the formation of Telangana under the AP Reorganisation Act in February 2014. Another NDA-ruled state, Bihar, is also demanding this status, with CM Nitish Kumar's cabinet having passed a resolution in November 2023. The stability of the Modi 3.0 government will hinge a lot on how far Naidu and Nitish will go for the sake of their respective states.

In contrast, things are pretty simple and straightforward for the BJP in Odisha, where tribal leader Mohan Charan Majhi has taken oath as the party's first CM in that state. The saffron party ended the Naveen Patnaik-led Biju Janata Dal's long reign with an impressive win in the recent Assembly elections. The challenge for Majhi would be to sustain the momentum of development that Odisha witnessed when Naveen was at the helm.

NEET fails to provide a level playing field

Merit must be measured in terms of societal good. The policy of 'one nation, one test' requires a serious review and improvement.

ISSUING notices to the National Testing Agency (NTA) and the Central Government on pleas seeking a fresh NEET-UG 2024 examination amid allegations of a paper leak, the Supreme Court's vacation Bench said, "Sanctity has been affected and we need answers." It has again been proven that NEET is not a neat way of testing students. There are serious allegations of paper leak and the possibility of an unfair advantage given to some candidates. Questions are being raised about the integrity of the test. Technical glitches, such as poor network connectivity, were faced by many students at a number of centres, leading to disruptions in the test.

An unusually large number of candidates have obtained high scores. As many as 67 candidates scored a perfect 720, with each scoring 99.997129 percentile. The fact that six of them were at the same centre has raised eyebrows. The grant of grace marks to around 1,560 candidates for the loss of time is also being criticised, as the NTA did not disclose details of the formula based on the Supreme Court's 2018 decision. The NTA's clarification is that candidates were compensated through grace marks. NEET is a unique system of admission. To pursue a medical course in India, one must clear this test. The idea of common tests was initiated by Murli Manohar Joshi when he was the HRD Minister in the then NDA government. It found some support in the judgement of the Supreme Court in TMA Pai Foundation vs State of Karnataka (2002). NEET was notified by the Medical Council of India (MCI) in 2010. But, in 2013, a three-Judge majority decision in Christian Medical College Vellore Association vs Union of India struck down NEET. The decision was widely criticised as anti-student and one that would lower the standards of medical education. As a result, the Indian Medical Council Act, 1956, was amended and Section 10D was inserted to empower the MCI to conduct NEET. A review petition against this judgment was allowed in 2016, and the apex court ordered the conduct of NEET from 2016 itself.

Surprisingly, the Bench did not accept the Government of

India's repeated requests to permit state governments to conduct their tests at least in 2016. Interestingly, the dissenting Judge of the 2013 judgment made NEET compulsory even prior to a full hearing by the Constitution Bench. NEET was thus imposed by the court and not the Narendra Modi government. The Justice Arun Mishra-led Bench in 2020 again upheld NEET, even in respect of minority institutions. Unfortunately, the top court considered just the legality of NEET and overlooked the real impact it would have on the ground, particularly on the underprivileged and minority institutions.

Why is NEET not really student-friendly? First, if a student falls ill or doesn't do well in the single test, he or she will not get a chance to qualify in another without losing a year. Second, it gives a student the right to select an institution of his or her choice by applying to particular institutions if multiple tests are conducted. In centralised NEET counselling, he ends up with colleges which he may not want to join.

The NEET paper leak has created problems for over 2.3 million candidates. There are translation-related errors in the question paper. NEET does not test qualities that a doctor must possess, such as compassion, empathy and passion to serve humanity. And finally, one single test is not the correct yardstick. Global best practices give weightage to marks in qualifying examinations, extracurricular activities and the statement of purpose.

But NEET is considered the best option, as our judges and the government think it promotes merit. But is there consensus on what merit really means? British sociologist Michael Dunlop Young's book *The Rise of the Meritocracy* (1958) popularised what is called 'meritocracy'. Meritocracy requires competition and equality of opportunity. Is it not a fact that the NTA and

judges believe that the multidimensional construct of merit can be adequately, if not accurately, measured?



When NEET and other such admission tests do not meet this fundamental criterion, competition cannot be termed as fair and just, and the equality of opportunity becomes illusory. There are scholars in the West who argue that common admission tests cannot measure abilities that are essential for learning, such as imagination, curiosity and motivation.

There is indeed an element of class in NEET, and the Justice AK Rajan Committee did find hard evidence of such elitism. The Justice Rajan report on the impact of NEET in Tamil Nadu substantiated arguments against a single test. A majority of the 86,342 people the panel

spoke to were opposed to NEET. The diversity in Tamil medical institutions has been affected with the introduction of NEET. The percentage of students from rural areas has dropped from 61.45 per cent to 50.81 per cent. Similarly, the percentage of candidates from government schools has gone down from 1.12 per cent to 0.6 per cent. The percentage of English-medium students — already dominating medical education — went up from 85.12 per cent to 98.01 per cent. For students from economically poorer sections, it was a decline — from 47.42 per cent to 41.05 per cent. The number of first-generation learners has also dipped. If similar committees are appointed in other states, we may get similar findings. The Tamil Nadu Assembly did pass a law against NEET in 2021, but the Governor returned it in 2022. On the resubmission of the Bill, the Governor referred it to the President, who is unlikely to give her assent. Moreover, with just one national test, commercial coaching institutes are making a lot of money. And since most of them are based in big cities, poorer students from a rural background and those who have studied in vernacular mediums remain

at a disadvantage. There is also large-scale variation in the syllabus when it comes to the CBSE and state boards. If unequals are tested on the basis of one test, ie EET, the mandate of equality is violated. We need to redefine our notions of merit in terms of a more inclusive and plural society. Merit cannot lead to exclusion. CJI DY Chandrachud rightly held that the transformative vision of the Constitution cannot be buried by the myths around 'merit'. Merit must be measured in terms of societal good. The policy of 'one nation, one test' requires a serious review and improvement.

Ambuja Cements shares gain 3%. Is there further upside

New Delhi. Ambuja Cements has received a bullish outlook from brokerage firms following its announcement to acquire South-based Penna Cement Industries Ltd (PCIL).

Jefferies has issued a 'buy' rating for Ambuja Cements, setting a target price of Rs 735 per share. The brokerage firm believes this acquisition will strengthen Ambuja Cements' position as a leading player in the Indian cement industry, particularly under the Adani group's ownership. Shares of Adani Group's Ambuja Cement surged by over 3% to Rs 689 in early trade on Friday to hit its 52-week high. The shares of the cement company rose on the back of the acquisition of Penna Cement Industries Ltd (PCIL) for Rs 10,422 crore.

Morgan Stanley anticipates that this deal will enhance Ambuja's presence in the southern market, reinforcing their bullish stance on the stock.

Emkay Global Financial Services maintained its preference for Ambuja Cements, keeping its 'Buy' recommendation and setting a target price of Rs 700 per share for March 2025. Similarly, Antique Stock Broking also upheld its 'Buy' rating for Ambuja Cements, with a target price of Rs 700 per share.

The deal was signed on Thursday and includes the purchase of 100% shares of PCIL from its current owners, P Pratap Reddy and family, as per a company filing to the exchanges. "Ambuja Cement, the cement and building material company of Adani Cement and part of the diversified Adani Group, today announced the signing of a binding agreement for the acquisition of Penna Cement Industries Ltd (PCIL) at an enterprise value of Rs. 10,422 crore. Ambuja will acquire 100% shares of PCIL from its existing promoter group, Mr. P. Pratap Reddy and family. The acquisition will be fully funded through internal accruals," said the exchange filing. Ambuja Cements will fund this acquisition entirely through internal accruals, as per the filing.

Ajay Kapur, CEO and Whole Time Director of Ambuja Cements, called this deal a significant milestone in the company's growth. "By acquiring PCIL, Ambuja is poised to expand its market presence in south India and reinforce its position as a pan-India leader in the cement industry," said Kapur.

Sensex, Nifty trade flat as IT stocks dip; Ambuja Cements gains 3%

New Delhi Benchmark stock market indices were trading flat in early trade on Friday due to a decline in information technology (IT) stocks. The S&P BSE Sensex rose 69.05 points to 76,879.95 at 10 am, while the broader NSE Nifty50 gained 31.4 points to 23,430.3. The other broader market indices also traded in positive territory as volatility dipped. Nifty Realty was the top gainer among sectoral indices, while Nifty IT fell 0.7% after gaining yesterday. The top five gainers on the Nifty50 were Grasim, Shriram Finance, Adani Ports, HUL and M&M. Meanwhile, shares of Adani-backed Ambuja Cements rose 3% in early trade after it acquired Penna Cement Industries. Dr. V K Vijayakumar, Chief Investment Strategist, Geojit Financial Services, said, "In the near-term the market is likely to be range bound since there are no major triggers till the budget."

"Since the valuations are high, particularly in the broader market, any significant up move will invite selling from the FIIs. If the market trends down, DIIs and retail investors will pursue a buy on dips strategy that has worked very well in this market," he added.

"Sustained flows into mutual funds, particularly through the SIP route, and the retail investors eager to buy any dip will keep the market resilient. Investors should now take a medium to long-term view and remain invested in the market focusing on fairly valued largecaps," Vijayakumar noted.

Hyundai Motor India recalls 1,744 units of Ioniq 5

NEW DELHI. Hyundai Motor India is recalling 1,744 units of its electric model Ioniq 5, due to an issue with the integrated charging control unit, as per the information available with industry body SIAM.

The company is recalling the units manufactured between July 21, 2022 and April 30, 2024, to fix the part, data on the SIAM website said.

The company is recalling the units due to a "potential issue in integrated charging control unit which may discharge 12V battery", it stated. When contacted, a Hyundai company spokesperson said: "At Hyundai Motor India, customer safety is our top priority. The Ioniq 5 recall is a proactive step to inspect and upgrade the Integrated Charging Control Unit (ICCU) in the affected vehicles at no cost to the customers."

The company's dedicated teams will be in touch with vehicle owners and guide them through the recall process, the spokesperson said.

Markets decline in early trade after record rally

MUMBAI. Benchmark equity indices declined in early trade on Friday amid profit-taking after a record rally in the previous day and fresh foreign fund outflows.

The 30-share BSE Sensex declined 206.18 points to 76,604.72. The NSE Nifty dipped 61.5 points to 23,337.40. Among the 30 Sensex companies, Tech Mahindra, JSW Steel, HCL Technologies, NTPC, Bajaj Finserv, Kotak Mahindra Bank, Wipro and Tata Consultancy Services were the major laggards. Titan, Asian Paints, Mahindra & Mahindra and Hindustan Unilever were among the biggest gainers.

In Asian markets, Seoul quoted higher while Tokyo, Shanghai and Hong Kong traded lower. US markets ended on a mixed note on Thursday. Foreign Institutional Investors (FIIs) offloaded equities worth Rs 3,033 crore on Thursday, according to exchange data. "In the near-term the market is likely to be range bound since there are no major triggers till the budget," said V K Vijayakumar, Chief Investment Strategist, Geojit Financial Services. Global oil benchmark Brent crude declined 0.41 per cent to USD 82.41 a barrel.

The BSE benchmark jumped 538.89 points or 0.70 to hit its lifetime peak of 77,145.46 on Thursday. It later ended at a fresh record high at 76,810.90; up 204.33 points or 0.27 per cent. The Nifty rallied 75.95 points or 0.33 per cent to settle at a new closing high of 23,398.90.

WPI inflation spikes to 2.61% in May led by food and fuel

Wholesale prices in India rose by 2.61% in May

The WPI Food Index climbed to 185.7 in May

Fuel and power index dropped by 2.71%

New Delhi. Wholesale prices in India rose by 2.61% in May, up from 1.26% in April, marking a notable increase driven by higher costs in the food and fuel sectors, according to data released by the Ministry of Commerce & Industry.

"The annual rate of inflation based on all India Wholesale Price Index (WPI) number is 2.61% (Provisional) for the month of May, 2024 (over May, 2023). Positive rate of inflation in May, 2024 is primarily due to increase in prices of food articles, manufacture of food products, crude petroleum & natural gas, mineral oils, other manufacturing etc," said the press release. The Wholesale Price Index (WPI), which tracks the average change



in prices at the wholesale level, saw a month-on-month increase of 0.20% compared to April. The spike in prices was particularly pronounced in food items and fuel. The WPI Food Index, encompassing

essentials like cereals, vegetables, milk, and meat, climbed to 185.7 in May from 183.6 in April. This increase led to a rise in inflation within the food category from 5.52% in April to

7.40% in May. Primary articles, including food and minerals, spiked up by 0.54% to 187.7 in May, reflecting higher prices in food articles and minerals by 1.48% and 1.08%, respectively. Meanwhile, non-food articles and crude petroleum prices showed a decline of 1.26% and 3.56% in May compared to April.

In contrast, the fuel and power index dropped by 2.71% to 150.6 in May, primarily due to a decrease in electricity prices by 11.67%. Prices of mineral oils and coal, however, remained unchanged. Manufactured products, another significant component of the WPI, recorded an increase of 0.64% to 141.7 in May from 140.8 in April.

Among the 22 groups tracked under manufactured products, 13 reported higher prices, 8 saw declines, and 1 remained steady.

Notably, sectors such as basic metals, food products, and electrical equipment saw price hikes, while fabricated metal products and chemicals experienced price reductions.

India set to remain fastest-growing economy in Asia-Pacific: Moody's

NEW DELHI Ratings agency Moody's said that India is expected to remain the fastest-growing economy in the Asia-Pacific region in 2024. This projection follows the momentum built in the previous year, driven largely by domestic factors.

In its report titled 'Credit Conditions - Asia-Pacific H2 2024 Credit Outlook,' released on June 13, Moody's highlighted that Indonesia, the Philippines, and India have led the growth in the first half of 2024. These countries are anticipated to continue performing well compared to pre-COVID growth levels, thanks to increasing exports, strong local demand, and substantial government spending on infrastructure projects.

"India will remain the region's fastest-growing economy, sustaining last year's domestically driven momentum. We anticipate policy continuity after the general election, and a continued focus on infrastructure development

and encouragement of private sector investment," said the report. The agency also mentioned that India and ASEAN economies are likely to see stronger portfolio inflows due to robust



corporate credit metrics and attractive valuations. Last month, Moody's Ratings forecasted that the Indian economy would grow by 6.6% in the current fiscal year. It noted that strong credit demand and robust economic growth would benefit the profitability of non-bank finance companies (NBFCs). "We expect India's economy

to expand by 6.6% in the year ending March 2025 (FY25) and 6.2% the following year. This will lead to strong loan growth at NBFCs, mitigating the impact of rising funding costs on their profitability," said Moody's Ratings. Moody's FY25 GDP growth predictions for India are lower than those of the Reserve Bank of India (RBI) and other agencies but align with Deloitte's forecast. The RBI had projected a 7% growth rate for the current fiscal year. Both the Asian Development Bank (ADB) and Fitch Ratings have also estimated growth at 7%, while S&P Global Ratings and Morgan Stanley expect a 6.8% growth rate. India's focus on infrastructure development and private sector investment is expected to continue driving its economic growth, making it a key player in the Asia-Pacific region's economic landscape.

US-Saudi petrodollar deal ends after 80 years: What are petrodollars

NEW DELHI The US-Saudi Arabia petrodollar deal, a pivotal arrangement in global finance, has ended after 80 years. This landmark deal, initiated on June 8, 1974, facilitated the exchange of US dollars for crude oil exports, bolstering the dollar's dominance. Petrodollars are not a currency but US dollars exchanged for crude oil exports.

The term "petrodollars" refers to the US dollars earned by oil-exporting countries through the sale of oil. The concept emerged in the early 1970s and has played a significant role in global economics and geopolitics.

History behind petrodollars
Initially, the Bretton Woods Agreement of 1944 established the US dollar as the world's primary reserve currency, pegged to gold. This facilitated international trade and economic stability post-World War II. However, in 1971, US President Richard Nixon ended the dollar's convertibility to gold, leading to floating exchange rates and increased currency volatility. In the following year, the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) imposed an oil embargo in response to US

Wholesale inflation rises for third straight month in May at 2.61%, food items costlier



NEW DELHI. The wholesale inflation rose for the third consecutive month in May at 2.61 per cent on account of rise in prices of food articles, especially vegetables, and manufactured items.

The wholesale price index (WPI) based inflation was 1.26 per cent in the previous month.

It was (-) 3.61 per cent in May 2023.

"Positive rate of inflation in May, 2024 is primarily due to increase in prices of food articles, manufacture of food products, crude petroleum & natural gas, mineral oils, other manufacturing etc," the Ministry of Commerce & Industry said in a statement on Friday.

As per the data, inflation in food articles rose 9.82 per cent in May, as against 7.74 per cent in April. Inflation in vegetables was 32.42 per cent in May, up from 23.60 per cent in the previous month. Onion inflation was at 58.05 per cent, while potato was 64.05 per cent.

Pulses inflation rose 21.95 per cent in May. In the fuel and power basket, inflation stood at 1.35 per cent, marginally lower than 1.38 per cent in April. In manufactured products, inflation was at 0.78 per cent, higher than (-) 0.42 per cent in April. The rise in May WPI is in contrast to the retail inflation data for the month. The Reserve Bank of India (RBI) mainly takes into account retail inflation while framing monetary policy.

Retail inflation eased to 1 year low of 4.75 per cent in May, data released earlier this week showed.

The RBI earlier this month kept the interest rate unchanged for the eighth time in a row.



support for Israel during the Yom Kippur War, causing oil prices to skyrocket. The US struck a deal with Saudi Arabia and other OPEC countries to stabilise the situation, where oil would be traded exclusively in US dollars. In return, the US provided military protection and economic support. This agreement marked the birth of the petrodollar system. US-Saudi petrodollar deal In 1974, amid an oil crisis and skyrocketing prices due to OPEC sanctions, the US and Saudi Arabia struck a crucial deal. The US agreed to buy oil from Saudi Arabia and provide military aid and equipment, while the Saudis would invest their petrodollar revenue back into the US economy. This arrangement ensured a steady flow of oil to the US and financial stability for Saudi Arabia, benefiting both nations.

What happens now?

With the deal's expiration, Saudi Arabia is now free to sell oil for currencies like yuan, euros, rubles, and yen, and is considering digital currencies like Bitcoin. This shift may accelerate the trend of using alternative currencies for international trade, potentially weakening the US dollar's global dominance.

Bank of Japan to scale down huge bond-buying programme

While the move had been widely expected, observers said the decision to defer action until next month weighed on the yen, pushing it towards 158 per dollar, from around 157.20.

TOKYO. The Bank of Japan on Friday said it would trim its vast hoard of government bonds as it cautiously steps away from its long-running ultra-loose monetary policy. The central bank kept interest rates unchanged after a two-day meeting but announced plans to "reduce its purchase amount of JGBs (Japanese Government Bonds) thereafter to ensure that long-term interest rates would be formed more freely". "A detailed plan" for the reduction "during the next one to two years or so" will be decided at the next policy meeting in July, it said. While the move had been widely expected, observers said the decision to defer action until next month weighed on the yen, pushing it towards 158 per dollar, from around 157.20.

However, news that borrowing costs would not go up for now lifted the benchmark Nikkei index 0.7 percent in the afternoon,



having been flat at the break. The BoJ raised rates in March for the first time since 2007 as it seeks to normalise policy without destabilising the world's fourth-largest economy. Friday's move marks another step away from more than two decades of quantitative easing designed to banish stagnation and harmful deflation. Each month, the BoJ targets monthly government bond purchases of around six trillion yen (\$38 billion), to pump liquidity into the system and keep borrowing costs down. The scale of the BoJ's total assets is enormous -- larger than the country's gross domestic product -- and the bank holds more than

half the value of all JGBs in circulation. Cutting back on bonds has been on the cards for months. Policymaker opinion cited in the minutes of the BoJ's April meeting said the bank should indicate an intention to do so because it "needs to reduce the size of its balance sheet".

'Fragile' economic recovery
Other central banks have aggressively hiked interest rates to tackle soaring inflation in recent years. But the BoJ has largely stuck to its easy-money policies -- culminating in the Japanese currency hitting a 34-year low in April that led authorities to step into forex

markets. "Reducing bond purchases is an important aspect for the Bank of Japan as it aims to normalise its monetary policy and support the yen," Wael Makarem, financial markets strategists lead at Exness, told AFP before the decision. "However, given Japan's fragile economic recovery and high public debt, the central bank may have to proceed cautiously," he said. The BoJ wants to see demand-driven inflation of two percent, fuelled by wage increases. Japanese inflation has been above the target since April 2022, but analysts question to what extent this is caused by temporary factors such as the war in Ukraine.

On Friday, the bank said factors including accommodative financial conditions were behind the gradual intensification of "a virtuous cycle from income to spending". But "there remain high uncertainties surrounding Japan's economic activity and prices", it said.

As well as calling time on its outlier negative-rate policy in March, the bank has stepped away from other unorthodox policies including its yield curve control programme, which allowed bonds to move in a tight band. "With inflation remaining somewhat sticky... a further rate hike in July or September is likely" although "the timetable for that may remain unclear."

Kuwait Building Fire: Plane Carrying Bodies Of 45 Indians To Land In Kochi

Kuwait Building Fire: Out of the 176 Indian workers in the housing facility, 45 have died, while 33 are hospitalised and the rest are reportedly safe.

New Delhi: India will bring back the bodies of 45 of its nationals killed in a devastating fire in Kuwait City on Wednesday by a special flight which will land in Kochi on Friday morning before heading for Delhi, the Indian Embassy in Kuwait said in a statement on Thursday night according to

the statement, most of the victims are from Kerala (23), followed by seven from Tamil Nadu, three each from Andhra Pradesh and Uttar Pradesh, two from Odisha, and one each from Bihar, Punjab, Karnataka, Maharashtra, West Bengal, Jharkhand, and Haryana. Minister of State for External Affairs, Kirti Vardhan Singh, acting on the directions of Prime Minister Narendra Modi, reached Kuwait on Thursday forenoon to coordinate with the Kuwaiti government for the early repatriation of the mortal remains of the victims as well as to ensure the well-being of those injured in the tragic fire incident at a labour housing facility in the Mangaf area on Wednesday, the statement said.

Out of the 176 Indian workers in the housing facility, 45 have died, while 33 are hospitalised and the rest are reportedly safe. Immediately upon his arrival, the Minister visited five hospitals (Adan, Mubarak Al-Kabeer, Jaber, Farwaniya and Jahra), where



the injured Indians are being treated, and interacted with them. According to hospital authorities, all the patients are reportedly safe and will be discharged progressively depending on their medical condition.

Vardhan Singh also called on First Deputy Prime Minister, Minister of Defence & Interior, Sheikh Fahad Yousef Saud Al-Sabah, who conveyed the condolences on behalf of Kuwait's ruler, Sheikh Meshal Al-

Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, and assured full support and assistance for early repatriation of mortal remains of the victims and proper medical care and attention to all those who are hospitalised.

The Minister also called on the Minister of Foreign Affairs, Abdullah Ali Al-Yahya, and Health Minister, Ahmad Abdelwahab Ahmad Al-Awadi, and both assured full support of the Kuwaiti government. The Embassy, expressing its deepest condolences to the bereaved families, said that it has been in constant touch with the local authorities, ensuring all necessary assistance to those injured and those who have been safely evacuated from the accident site.

It said it has been operating a dedicated 24x7 helpline +965-65505246 (Whatsapp and regular call) for the family members of the victims as well as those injured. Regular updates are being provided through the helpline.

Parliament Monsoon Session from July 22 to August 9: Sources

New Delhi: The Monsoon Session of Parliament is set to begin on July 22, sources have said. The session is likely to continue until August 9. The government is also likely to present the full Budget for 2024-2025 during the Monsoon Session, with the Finance Ministry starting its pre-consultation Budget meetings with various ministries and stakeholders by June 17. The Session is also likely to cover the oath/affirmation of newly elected members, the election of the speaker, the President's address, and subsequent discussions.

Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijju in a post on X said that the first session of the 18th Lok Sabha will be held from June 24 to July 3. On February 1, Finance



Minister Nirmala Sitharaman announced the Interim Budget 2024-25, highlighting the government's economic achievements during the past 10 years and how the nation has transformed into one of the fastest-growing economies in the world. The Finance Minister maintained the government's focus on creating jobs through a sustained infrastructure push, in addition to prioritising groups such as farmers, youth, women, and the poorest households. Meanwhile, a special 8-day session of Parliament is slated to commence on June 24, during which, the election of the Lok Sabha speaker is likely to be held on June 26, sources told India Today. On June 24 and 25, new Members of Parliament will be taking their oaths, according to the sources.

2 Minors Among 6 Held For 70 Lakh Heist In Delhi

New Delhi: Delhi Police has apprehended six people, including two minors who were involved in a robbery case of ₹ 70 lakh in Naya Bazar of Chandni Chowk the national capital. Delhi Police has apprehended six people, including two minors who were involved in a robbery case of ₹ 70 lakh in Naya Bazar of Chandni Chowk in Delhi. The heist took place at the Govind Agency in Naya Bazar in the Lahori Gate area of



Chandni Chowk on June 9. According to complainant Chaggo Mal Pande, 76, who worked as a cash collection staff at Govind Agency, he was robbed at gunpoint of approximately ₹ 23 lakh in cash. Additionally, another bag containing uncounted money was also taken, he said. An eight-member team of Delhi Police carried out searches in Mussoorie, Dehradun, and Delhi and arrested six suspects within 28 hours. Total cash amounting to ₹ 30 lakh was also recovered. Delhi Police said acting on crucial CCTV footage and technical surveillance, the police were able to trace the movements of the suspects and arrested them within 28 hours of the crime being reported. Three accused identified as Chinar Amariya (23), Paras (20), and Sharad (19) along with a juvenile were apprehended from Mussoorie and ₹ 14.3 lakh cash was recovered from them. Shares worth ₹ 1.2 lakh and one R1 bike was also seized. Rest of the three accused including Rohit (20) were apprehended from Dehradun along with ₹ 9.4 lakh cash and three phones worth ₹ 4.5 lakh, which were purchased from looted money. Two suspects are yet to be apprehended. Delhi Police team said it is conducting continuous raids to apprehend these suspects and recover the rest of the stolen money.

After 7 Paroles In 10 Months, Rape Convict Ram Rahim Seeks Yet Another

New Delhi: Rape convict Gurmeet Ram Rahim has filed another petition in the Punjab and Haryana High Court for a 21-day parole. The Dera Sacha Sauda chief was granted a 50-day parole in January - for a seventh time in just 10 months. Ram Rahim in his petition said he needed the parole to participate in a programme hosted by the Dera Sacha Sauda. After admitting his petition, the high court issued notice to the Haryana government and the Sikh Gurdwara Prabandhak Committee (SGPC), and sought a reply by July 2.

The high court on January 29 had raised questions over repeated paroles granted to the rape convict who is supposed to be serving 20



years in jail.

After that, the high court had ordered the Haryana government to take its permission if he approaches for parole again. Responding to a petition by the SGPC, the court had also ordered the state government to give information on how many

people have been given parole in this manner. Sources have said there had been a pattern behind granting paroles to the rape convict, and it usually happened during state or local body polls. Dera followers, and particularly those of Ram Rahim Singh, are influential in Punjab's Malwa region, with their votes seen as key in deciding parliamentary and legislative elections. The Malwa region has

69 constituencies - over half of the Punjab assembly's 117 seats.

Dera followers - who number in the crores and have been relatively subdued since Ram Rahim Singh was jailed - are widely seen as voting per diktats from sect leaders.

How Cops Busted Gang Involved In Issuing Fake Caste Certificates In Delhi

New Delhi: Delhi Police have busted a gang involved in issuing fake caste certificates to applicants from non-reserved categories. Four persons have been arrested, including a Tehsildar from Delhi Cantt, Department of Revenue and Government of NCT of Delhi. The police said that they received information about a gang creating and distributing fake caste certificates. To verify this, on March 13, 2024, a decoy applicant from the General Category was sent to a suspected person to obtain an OBC certificate. The decoy applicant received the certificate for a fee of ₹ 3,500, which was also uploaded on the Delhi Government's Revenue Department website.

Another decoy operation was conducted on March 20, 2024, where a second

applicant from the General Category obtained an OBC certificate for ₹ 3,000. Both payments were made online, and transaction details were recorded. Based on this information, a police team was formed to apprehend the individuals behind the racket.

On May 9, 2024, Saurabh Gupta, a 30-year-old resident of Sangam Vihar, was arrested. Data from his mobile phone revealed chats with the decoy applicants and various document snapshots. Gupta admitted to issuing the certificates through the Executive Magistrate's office in Delhi Cantt. Further investigation led to the arrest of three more individuals: Chetan Yadav, who worked at the Tehsildar's office, Waris Ali, the civilian driver of Tehsildar Narender Pal Singh, and Narender Pal Singh himself. These arrests took place on

May 14, May 22, and May 27, 2024, respectively. According to the police, Gupta disclosed that he met Chetan Yadav in January 2024. Together with Waris Ali, they devised a scheme to earn money by issuing fake certificates from the Department of Revenue.

Gupta would apply for certificates using fake documents and then share the details and application numbers with Yadav, transferring money for each case.

Yadav would forward these details to Waris Ali, who used the Digital Signature (DS) of Executive Magistrate Narender Pal Singh to approve the applications and upload the certificates on the website. The gang charged fees and split the money among themselves, including paying the Executive Magistrate.

Importance Of Puri Jagannath Temple's Four Gates: Why It Was A Poll Issue

New Delhi: The 12th-century Shree Jagannath Temple in Odisha's Puri, one of the Char Dham pilgrimage sites in India, opened all four gates on Thursday after persistent demands from devotees. This decision came shortly after the new BJP government in Odisha, led by Chief Minister Mohan Majhi, approved the move in its first Cabinet meeting.

Puri's Shree Jagannath Temple's four gates: Significance

These gates have been part of the temple's architecture and rituals since ancient times. Each gate is associated with a specific direction and symbolism: Singha Dwara (Lion's Gate): Located in the east, it is considered the main entrance and symbolises liberation (moksha). Entering through this gate is believed to lead a devotee towards spiritual liberation. Vyagra Dwara (Tiger Gate): Positioned in the west, it symbolises righteousness (dharma). Passing

through this gate is seen as upholding moral and ethical values. Hasti Dwara (Elephant Gate): In the north, it represents prosperity and wealth. This gate is regarded as the carriage of Maha Lakshmi, the goddess of wealth.

Ashwa Dwara (Horse Gate): Located in the south, it symbolises desire (kama). It is said that entering through this gate requires one to overcome worldly desires and attachments.

Why were they closed?

The gates of the temple were closed initially during the COVID-19 pandemic primarily for safety reasons and to comply with public health guidelines. This measure was part of efforts to mitigate the spread of the virus among devotees and temple staff.

Some of them were kept closed to facilitate ongoing renovation work related to the Srimandir Heritage Corridor project, a significant initiative aimed at preserving and enhancing the

temple's historical and cultural heritage. Why was the Jagannath Temple an issue during the elections? During the 24-year rule of the BJD in Odisha, one of the major controversies surrounding the temple was the missing keys to the Ratna Bhandar (inner treasury where



precious jewellery and stones are kept). The former state government led by Naveen Patnaik's BJD, was also accused of not maintaining records and inventories of the temple's treasures properly. Transparency issues and allegations of mismanagement, especially concerning the temple's valuable assets, further fueled

Army gets Nagastra-1, India's first indigenous suicide drone

NEW DELHI: In a significant stride towards achieving 'atmanirbharta' (self-reliance) in ammunition and defence systems, the Indian Army is set to induct its first indigenous loiter munition, Nagastra-1. Developed by Solar Industries, Nagpur, the Army has placed a supply order for Economics Explosives Ltd (EEL), a 100 per cent subsidiary of Solar Industries, to supply 480 loiter munitions. Following a successful Pre-Delivery Inspection (PDI) from May 20-25, EEL delivered the first batch of 120 units to the ammunition depot at Pulgaon. The Nagastra-1 excels in "kamikaze mode" by neutralising hostile threats with GPS-enabled precision strikes, boasting an accuracy of up to two metres. Weighing 9 kg, this man-portable fixed-wing electric UAV has an endurance of 30



minutes. It offers a 15 km range with man-in-loop control and extends up to 30 km in autonomous mode. Due to its electric propulsion system, Nagastra-1 provides a low acoustic signature, making it almost undetectable at altitudes over 200 metres.

The UAV is equipped with day and night surveillance cameras and carries a 1 kg high-explosive fragmenting warhead to neutralise soft-skin targets. Its unique features like abort, recover and reuse, facilitated by a parachute recovery mechanism, set it apart from similar systems globally. Designed with over 75 per cent indigenous content in collaboration with Z-Motion Autonomous Systems Pvt Ltd, Bengaluru, Nagastra-1 is a man-portable system with an all-up weight of 30 kg split across two rucksacks, including a ground control station, communication control, payload and pneumatic launcher. The success of Nagastra-1 builds on the potential of drone technology as a force multiplier in military operations, as evidenced in recent conflicts in countries such as Armenia, Azerbaijan, Syria, Saudi Arabia, Russia and Ukraine. In the Indian context, there has been a rise in drone-related incidents along its northern borders, underscoring the need for such indigenous solutions. Most industries in India lack the expertise for weaponised drones in combat applications.

discontent. Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah also voiced concerns about the temple's sanctity and management practices under the BJD rule. They highlighted issues such as the commercialisation of the temple precincts, the demolition of traditional institutions and the closure of certain temple gates, which was perceived as compromising the temple's traditional practices and religious integrity. Controversies surrounding the temple's management and events like the Rath Yatra (chariot festival) also added to the overall public discourse and scrutiny during the elections. In their election manifesto, the BJP pledged to open the remaining gates of the Jagannath Temple once in power in the state. The newly appointed Chief Minister, Mr Manjhi, has now allotted ₹ 500 crores for the temple's management, beautification and repair.

NEWS BOX

Elon Musk's shoutout to Trump at Tesla meet, says he 'calls me for no reason'

World Elon Musk has revealed former US President Donald Trump calls him up sometimes out of the blue "for no reason". Onstage at Tesla's annual shareholder meeting in Austin, Texas, Musk also said Donald Trump was a huge fan of the Cybertruck. "I don't exactly know... I have had some conversations with him, and he does call me, out of the blue, for no reason... I don't know why, but he does," Musk said. "And it's like he's very nice when he calls, and I was like electric cars, I think are pretty good for the future. America's leaders like electric cars, buy America and stuff," he joked. "I think a lot of his friends now have Teslas, and they will love it, and he's a huge fan of the Cybertruck, so I think those may be contributing factors," Musk said. Earlier, Trump had praised Elon Musk at a rally in Arizona saying he was a "big fan" of both electric vehicles and the Tesla boss.

MUSK WINS SHAREHOLDER APPROVAL FOR \$56 BILLION PAY PACKAGE

Tesla TSLA.O shareholders approved CEO Elon Musk's \$56 billion pay package, the electric vehicle maker said on Thursday, a big thumbs-up to his leadership and an incentive to keep his focus on his biggest source of wealth. The approval underscores the support that Musk enjoys from Tesla's retail investor base, many of whom are vocal fans of the mercurial billionaire. The proposal passed despite opposition from some large institutional investors and proxy firms. Onstage at the annual shareholder meeting in Austin, Texas, Musk described himself as pathologically optimistic. "If I wasn't optimistic this wouldn't exist, this factory wouldn't exist," Musk said to applause. "But I do deliver in the end. That's the important thing." He had tipped off late on Wednesday that the proposals were garnering huge support. The approval does not, however, resolve a lawsuit on the pay package in a Delaware court, which some legal experts think could stretch out for months. The judge invalidated the pay package in January, describing it as "unfathomable."

Spiraling criminal violence causes morgue to overflow, foul odors to spread in Ecuadorian city

KOLLAM: A devastating fire in the southern Mangaf district of Kuwait claimed the life of Umarudheen Shameer, a 33-year-old native of Kollam, along with 48 others, mostly Indians. The blaze, which occurred on Wednesday, left dozens more injured. Shameer, hailing from Sooranad North, had been working in Kuwait for the past seven years.

Relatives were informed of the tragedy around noon on Wednesday. According to family sources, the bodies have been moved to a local government hospital. It is suspected that Shameer died while attempting to jump from the building in a panic. The repatriation of his body is expected to take several days. Shameer had returned to Kuwait on Wednesday. He was the son of Umarudheen and Sheebna and had one younger brother, Nijaz, who is in class 8. His father, known locally as Raju Mesthiri and has been working as a contractor of home construction. Shameer was married to Surumi, a PSC aspirant. The family had previously resided in Oyoor village for 15 years before

US sheriff deputies responding to distress call shot at, suspect wounded

Quito Spiraling criminal violence in one of Ecuador's most dangerous cities caused a buildup of unidentified and unclaimed bodies that exceeded the capacity of Guayaquil's main morgue, officials confirmed Thursday. The government of Guayas, the province of which Guayaquil is the capital, said Thursday afternoon in a statement that "the problem that has arisen in recent days in the morgue" has been resolved, its first acknowledgement that the problem existed in the first place. Local television and media reports had said about 200 bodies over the Forensic Medicine Service morgue's capacity had accumulated and a refrigeration unit used to store them had failed, causing nearby residents to complain of foul odours. Ecuadorian media outlets Ecuavisa and



Teleamazonas broadcast images taken with drones showing morgue workers removing bodies from a refrigerated container and spraying the container's entrance with a product the outlets said was meant to neutralize the putrid liquids seeping out of it.

Both the Forensic Medicine Service and the Ministry of Health did not respond to requests for information from The Associated Press made on Wednesday.

The government statement did not say how many bodies were involved but said a malfunctioning refrigerated unit where bodies are kept when the morgue is full had been repaired. During the past week, forensic services collected 40 bodies that were victims of violence in a city that in 2023 recorded a total of 3,762 violent deaths, according to police figures. Most of the deaths are the result of clashes between gangs fighting over territory and drug distribution routes, which has created unprecedented levels of violence in this port city of 2.72 million inhabitants.

The former head of forensic medicine at the Guayaquil morgue, Juan Montenegro, told the AP that the "bodies are stored in containers without taking into account their cooling capacity," meaning the decomposition process is accelerated and bad odors spread and putrid liquids seep untreated into pipes. "I don't understand why they haven't sent the bodies to a mass grave in a timely manner, donated them to the universities, or why they haven't handed them over to the relatives, who are on the street demanding the bodies," he said.

Biden, Volodymyr Zelenskyy sign defence deal as Ukraine nears NATO membership

Borgo Egnazia, Italy US President Joe Biden and Ukraine President Volodymyr Zelenskyy signed a 10-year bilateral security agreement on Thursday aimed at bolstering Ukraine's defence against Russian invaders and getting Ukraine closer to NATO membership. The deal, signed on the sidelines of the G7 summit in Italy, aims to commit future US administrations to support Ukraine, even if former President Donald Trump wins November's election, officials said. "Our goal is to strengthen Ukraine's credible defence and deterrence capabilities for the long term", Biden said at a joint news conference with Zelenskyy. He said the G7's message to Russian President Vladimir Putin is "You cannot wait us out. You cannot divide us". The group of rich nations also agreed to a \$50 billion loan for Ukraine backed by profits from frozen Russian assets.

The US-Ukraine security deal is a framework for a long-term effort to help develop Ukraine's outdated armed forces and serve as a step towards Ukraine's eventual NATO membership, according

to the text. The Ukraine president called the agreement historic, saying it is a bridge toward his country's eventual NATO membership. "This is an agreement on security and thus on the protection of human life", he said. Zelenskyy has long sought NATO membership, but the allies have stopped short of taking that step. The Western alliance regards any attack launched on one of its 32 members as an attack on all under its Article Five clause.

In the event of an armed attack or threat of such against Ukraine, top US and Ukrainian officials will meet within 24 hours to consult on a response and determine what additional defence needs are required for Ukraine, the agreement says. Under the agreement, the United States restates its support for Ukraine's defence of its sovereignty and territorial integrity, amid a renewed push by Russia on Ukraine's eastern front. It also outlines plans to develop Ukraine's



own defence industry and expand its military. Ukraine needs a "significant" military force and sustained investments in its defence industrial base consistent with NATO standards, the text says.

It will allow the two countries to share intelligence, hold training and military education programs and combined military exercises. With Trump leading Biden in many election polls, the future of the agreement remains unclear. Trump

has expressed scepticism of Ukraine's continued fight, saying at one point that he would end the conflict on his first day in office. Trump has also pushed for Europe to take on more of the burden of supporting Kyiv. Zelenskyy, asked about what could happen for his country if there is a change in leadership in the United States and in other allied nations, said people stood with Ukraine because they have shared values and empathise with the Ukrainian people.

He said he does not think that popular support will change.

"If the people are with us, any leader will be with us in this struggle for freedom", he said. Biden recently shifted his policy against allowing Ukraine to use American weapons for attacks inside Russia, permitting Kyiv to fire long-range US missiles against Russian targets near the embattled Ukrainian city of Kharkiv.

US man threatens to 'slaughter' FBI agent over Hunter Biden gun case, charged

A 43-year-old man from Texas was charged with making threatening communications against an FBI agent over the gun case involving President Joe Biden's son Hunter Biden, who was convicted, on June 11.



Washington DC A Texas man was charged on Thursday with threatening to jail or "slaughter" an FBI agent over the criminal case against President Joe Biden's son, Hunter Biden, federal prosecutors said. Timothy Muller, 43, was charged in a criminal complaint with making threatening communications across state lines and "influencing, impeding or retaliating" against a federal official.

It was not immediately clear if Muller, of Fort Worth, had retained an attorney in the case, which was filed in the US District Court for the Northern District of Texas. Prosecutors referred to Hunter Biden only by the initials "HB" but the dates of the criminal case against him match those of the president's son. According to the criminal complaint, Muller on June 11 called an FBI agent who had been

assigned to investigate a laptop belonging to Hunter Biden. When the agent disconnected the call, Muller called again and left a threatening voice message, the complaint alleged. Biden on June 11 was convicted of lying about his illegal drug use to buy a gun. Prosecutors say Muller accused the agent of covering up crimes committed by Biden and said that if former US President Donald Trump were elected in November, the FBI agent would be jailed.

"Or, you can steal another election, and then the guns will come out, and we'll hunt you down and slaughter you like the traitorous dogs you are in your own homes in your own beds," Muller said in the message, according to the criminal complaint.

Canadian man stole Tesla trade secrets, tried to sell them to government agents

Canadian national Klaus Pflugbeil stole Tesla TSLA.O electric-vehicle battery manufacturing trade secrets and conspired to sell them to undercover government agents.

New York. A Canadian resident of China pleaded guilty in New York federal court on Thursday to stealing Tesla TSLA.O electric-vehicle battery manufacturing trade secrets and conspiring to sell them to undercover government agents, according to the US Department of Justice (DOJ). Klaus Pflugbeil, 58, the operator of a China-based business that sells technology used in electric vehicles, faces up to 10 years in prison for plotting with business partner Yilong Shao to sell

Tesla's secrets to FBI agents posing as Long Island businesspeople, the department said in a statement. Neither Pflugbeil's attorney nor representatives for Tesla immediately responded to Reuters requests for comment. Shao, who was also charged but remains at



large, could not be reached for comment. With his guilty plea, Pflugbeil is now being held accountable for this unlawful conduct that jeopardised our national security",

US Assistant Attorney General Matthew Olsen said in a statement. Pflugbeil, who is also a citizen of Germany, was charged in New York in March. Prosecutors said Pflugbeil and Shao built their EV battery business on trade secrets from a "leading US-based electric vehicle company".

Prosecutors did not name the company but said it acquired a Canada-based manufacturer of battery-assembly lines in 2019, which matches the description of Tesla's acquisition of Canadian company Hibar.

Thursday's statement said that Pflugbeil and Shao both worked for the Canadian company before Pflugbeil joined Shao's business in 2020. The DOJ said that the unnamed business now has locations in China, Canada, Germany and Brazil, making the same battery-assembly equipment as their previous employer.

US Supreme Court junks bid to prevent access to abortion pill mifepristone

Washington DC. The US Supreme Court rejected a bid by anti-abortion groups and doctors to restrict access to the abortion pill, handing a victory on Thursday to President Joe Biden's administration in its efforts to preserve broad access to the drug. The justices, two years after ending the recognition of a constitutional right to abortion, ruled 9-0 to overturn a lower court's decision to roll back US Food and Drug Administration steps in 2016 and 2021 that eased how the drug, called mifepristone, is prescribed and distributed. The decision was authored by conservative Justice Brett Kavanaugh. The pill, given FDA regulatory approval in 2000, is used in more than 60 per cent of US abortions. The justices ruled that the plaintiffs, who sued in Texas in 2022, lacked the necessary legal standing to pursue the case, which required that they show they have been harmed in a way that can be traced to the FDA.

The Supreme Court, which has a 6-3 conservative majority, in 2022 overturned its 1973 Roe vs Wade precedent that had legalised abortion nationwide, prompting 14 states to enact measures banning or sharply restricting the procedure.

Biden, a Democrat seeking a second term in office in the November 5 US election, took aim at Republican officials behind such bans, saying they want to outlaw abortion nationwide and that Thursday's ruling "does not change the fact that the

fight for reproductive freedom continues". "It does not change the fact that the Supreme Court overturned Roe v. Wade two years ago, and women lost a fundamental freedom. It does not change the fact that the right for a woman to get the treatment she needs is imperilled if not impossible in many states," Biden added. Kavanaugh wrote that even though the plaintiffs, led by a group called the Alliance for Hippocratic Medicine, do not prescribe or use mifepristone, they wanted the FDA to make it harder for other doctors to prescribe it and women to receive it. "Under Article III of the Constitution, a plaintiff's desire to make a drug less available for others does not establish standing to sue," Kavanaugh wrote, referring to the constitutional provision laying out the authority of the US government's judicial branch.

Kavanaugh rejected the argument made by the plaintiffs that the FDA's actions will force them to provide abortions, violating their consciences, because federal law already protects them. A ruling in favour of the plaintiffs could have threatened the regulatory authority of the FDA over drug safety. The plaintiffs targeted FDA regulatory actions in 2016 and 2021, including allowing for medication abortions at up to 10 weeks of pregnancy instead of seven, and for mail delivery of the drug without a woman first seeing a clinician in-person. The suit initially had

sought to reverse FDA approval of mifepristone, but that aspect was rebuffed by a lower court. Biden and other Democrats have sought to make abortion rights a central theme against Republicans in the election. Biden said he



will continue to urge Congress to codify abortion rights in federal law. Biden noted that some state abortion bans include no exceptions for rape or incest.

"Women are being turned away from emergency rooms, or forced to go to court to plead for care that their doctor recommended or to travel hundreds of miles for care," Biden said. "Doctors and nurses are being threatened with jail time, including life in prison, for providing the health care they have been trained to provide. And contraception and IVF (in vitro fertilisation) are under attack," he added. The Supreme Court by the end of June is expected to rule on the legality of Idaho's strict Republican-backed abortion ban that forbids terminating a

pregnancy even if necessary to protect the health of a pregnant woman facing a medical emergency. In the 14 states that have banned abortion with limited exceptions, medical providers cannot prescribe or dispense mifepristone under state law. Patients in those states might continue to take the legal risk of ordering the pills online from providers in other states or they might travel out-of-state to legally obtain the pills.

THE FIGHT OVER MIFEPRISTONE

Erin Hawley, a lawyer with the Alliance Defending Freedom, a conservative Christian legal group representing the plaintiffs, expressed disappointment with the ruling, but said it was on a "legal technicality" and not the merits of the legal arguments. The plaintiffs argued that the FDA acted contrary to its mandate to ensure that medications are safe when it eased restrictions on mifepristone. The plaintiffs accused the FDA of violating a federal law governing the actions of regulatory agencies. Hawley said she expected the litigation to continue given that three states - Idaho, Missouri and Kansas - already have intervened in it.

"We are very hopeful that the federal courts will have a chance to hold the FDA accountable for its unlawful actions in removing these long-standing safeguards for women," Hawley said.

NEWS BOX

'I get in trouble when...': US official's banter on Pak upset at T20 World Cup

White House official Matthew Miller was asked to comment on the USA cricket team defeating Pakistan in the T20 World Cup. In a cheeky response, Miller said he would "get into trouble" if he spoke on matters that were not his area of expertise.

US State Department spokesperson Matthew Miller indulged in fun banter with a reporter when he was asked about the USA cricket team shocking Pakistan in the ongoing ICC Men's T20 World Cup.

During a press briefing, Miller was asked by a reporter to comment on the USA, an associate team, winning against Pakistan, a full-member team. In a cheeky response, the official said he would "get into trouble" if he spoke on matters that were not his area of expertise. "I often get in trouble when I try to comment on things beyond my area of expertise, and I would say Pakistan's cricket



team is certainly in that category," Miller said. Miller's response underscores the fact that cricket, despite its global following, remains relatively niche in the US. Other sports like football, basketball or baseball are a rage in the country. However, with the US hosting a major cricket tournament for the first time, the ICC is hoping to gain more followers after the USA cricket team's historic showing so far. On June 6, the USA cricket team stunned Pakistan and registered its first-ever victory at the Grand Prairie Stadium in Dallas. The match went into a Super Over after both sides scored 159 runs.

In a game which had loads of twists and turns, it was the USA that emerged victorious over a hapless Pakistani side, who were guilty of dropping catches and misfielding at critical junctures. This is the first time that the US is hosting a major ICC cricket tournament with the West Indies as its co-host. India is leading the table in Group A, followed by the USA in second place with four points after two wins and one loss.

Rashid Khan ecstatic after Afghanistan book Super 8 berth: Boys made it easy for me

New Delhi. Rashid Khan was over the moon after Afghanistan stormed their way into the Super 8 of the T20 World Cup 2024. On Friday, June 14, they defeated Assad Vala's Papua New Guinea (PNG) by 7 wickets in a Group C match at the Brian Lara Stadium in Tarouba, Trinidad. With 6 points and a net run rate of +4.230 thanks to wins in both their matches, the Afghans also went back to the top of the table. Rashid lauded Fazalhaq Farooqi and Rahmanullah Gurbaz for putting their hands up and taking Afghanistan through to the second round. Farooqi picked up 3 wickets against PNG and is sitting on top of the charts with 12 scalps to his name. Gurbaz, meanwhile, is the top run-scorer in the mega event with 167



runs at an average of 55.66. I am feeling great to qualify for the next round. It has been a great effort from the boys since game one. They know what they to do and have executed beautifully, making things easy for me. It is important to have someone like him, Gurbaz who goes out and takes on the bowling or Farooqi who picks up wickets in the powerplay," Rashid said in the post-match presentation ceremony. "If the batter is attacking, then as a bowler you have to attack too, especially with pitches helping you. They have given us good starts in the last two games and today was a good opportunity for the others to spend some time in the middle," Rashid said.

Everyone has the skill to adjust

After fielding first, Afghanistan bowled PNG out for 95 in 19.5 overs. Thereafter, Gulbadin Naib stayed out for 49 as they romped home with 29 balls to spare. Rashid said that domestic cricket and knowledge of the conditions in the West Indies have helped the Afghan cricketers. "We had a domestic competition before coming here and everyone are in form. That is the beauty of playing franchise cricket, as you know the conditions, some of them have played at St Lucia and know how the pitch will play which will help others.

If David Warner opens the bowling, it would be funny: Michael Jones before AUS vs SCO

T20 World Cup 2024: Michael Jones suggested that it would be really funny if David Warner would open the bowling for Australia during the match against Scotland. He also light-heartedly welcomed Josh Hazelwood's suggestion on going easy against Scotland.

New Delhi. Scotland's opener Michael Jones welcomed Josh Hazelwood's remarks, suggesting that Australia might go easy on them during the Group B match at the Darren Sammy National Cricket Stadium in St Lucia on June 16, Sunday. Jones even joked about it and said that he would like to see David Warner opening the bowling for

Australia during the match. Speaking at the post-match press conference after Australia's win against Namibia, Hazelwood suggested that they might look to "drag it" against Scotland, if they get into a winning position, in order to affect England's team's net-run-rate. However, Australian captain Mitchell Marsh will get a one-match ban if Australia intends to manipulate the result against Scotland to knock England out of the T20 World Cup 2024.

The Scotland team seems to have been enjoying the banter between 2 arch-rivals England and Australia as they take a relaxed approach heading into the encounter. Former Australian captain Tim Paine also suggested that "the Australian team should go for a holiday and the England team should pack their bags." Jones suggested that he also enjoyed Paine's remarks, and he is looking forward to see if Scotland would benefit from this banter.

"I was watching it live actually, laughing to myself," Jones told the Press Association of Hazelwood's comments. "I watched that



interview and I watched Tim Paine when he was saying they should field half a side. I'm not particularly close to them, I don't know any of the Australian players, but it would be good if we could have a little word and sort something out," Jones added. Will David Warner open? "The rivalry between England and Australia is massive. If they want to play that way then happy days. We won't be

complaining. If they want to let David Warner open the bowling or something like that it would be pretty funny."

Scotland would need to beat Australia in order to edge past England in the Super 8 stage. England have shot up their net-run-rate above Scotland after an 8-wicket win over Oman.

Jones was eager to take on Australia and suggested that the Mitchell Marsh-led side would put up a tough fight against Scotland.

"At the end of the day our team wants the best result we can get, but on a personal level you want to challenge yourself against the best," he said. "The Australians are renowned for being extremely diligent and extremely professional. I'm absolutely certain they will come out

all guns blazing like they do for every game at every tournament.

"I almost hope they do go full strength on Saturday and we can show the cricket world we're up to the challenge. I'm absolutely certain they will come out all guns blazing like they do for every game at every tournament."

How Fazalhaq Farooqi drew strength to steer Afghanistan into T20 World Cup Super 8

New Delhi. Afghanistan (AFG) fast bowler Fazalhaq Farooqi revealed his success mantra after registering match-winning figures of 3/16 in four overs against Papua New Guinea (PNG) in Match 29 of the T20 World Cup 2024 on Friday, June 14 at Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad. Notably, Afghanistan beat PNG by seven wickets to register their third consecutive win of the tournament and qualify for the Super 8 stages.

Farooqi was adjudged Player of the Match for his performance as he helped his side bundle out PNG for just 95 in 19.5 overs. Reflecting on his performance, the 23-year-old spoke about his preparations heading into the tournament and expressed disappointment for not getting a single chance to play for SRH in the Indian Premier League 2024. The right-arm seamer also revealed his bowling plans and said that he's always looking for wickets irrespective of the conditions.



"I want to congratulate people of Afghanistan for qualifying to the Super 8, I think we've played some good cricket. I was in the IPL, unfortunately I didn't get a game, so I came here and gave myself the strength to come and perform. I have two plans while bowling - just get wickets if there's any swing or seam, if there's no movement, I just bowl in the right areas and keep it simple. We just need to give our 100% and do our best (in the Super 8)," said Farooqi in the post-match

presentation. Afghanistan become second team to qualify from Group C. Afghanistan took 15.1 overs to chase down the target of 96 as Gulbadin Naib remained unbeaten on 49* (36). Following their win, they became the second team to qualify for the Super 8 stages of the tournament from Group C after West Indies. Afghanistan's win meant the end of the road for New Zealand in the tournament.

The Kane Williamson-led side got off to a disastrous start to the event losing their first game against Afghanistan by 84 runs followed by a narrow 13-run loss against the West Indies. Meanwhile, Afghanistan will next take on West Indies in their last Group game on Monday, June 17 at Daren Sammy National Cricket Stadium, Gros Islet, St Lucia. The Rashid Khan-led side will look to continue their winning momentum in the upcoming fixture and head into the Super 8s unbeaten.

T20 World Cup: Team India arrive in Florida ahead of last Group game against Canada

The Indian Cricket Team arrived in Florida ahead of their last match of Group A in the T20 World Cup 2024 against Canada on Saturday, June 15 at Central Broward Regional Park Stadium Turf Ground. The Men in Blue have qualified for the Super 8 stages of the tournament having won three matches on the trot against Ireland, Pakistan and USA played in New York.

Having played their last game at the Nassau County International Cricket Stadium, India will now move to Florida before the action shifts to the West Indies for the Super 8 stage. The BCCI (Board of Control for Cricket in India) shared glimpses of their journey from New York to Florida as all the players looked rejuvenated after a day's break. In a video shared by the BCCI on their X handle, left-arm seamer Khaleel Ahmed expressed excitement about visiting Florida after a gap of five years and recalled India's tour to the West Indies in 2019. Further ahead in the video, Mohammed Siraj and



Yuzendra Chahal were seen getting involved in a hilarious banter regarding the Indian snack 'Samosa'. USA and Pakistan in battle for second spot in Group A

Meanwhile, India are on top in Group A with three wins from as many matches having a positive net run rate of +1.137. The Rohit Sharma-led side will look to continue their winning momentum against Canada before advancing to the Super 8s. Apart from India, the USA are the second favourites to advance to the next stage from Group A having won two out of their three matches so far.

They will be up against Ireland in their last Group game on Friday, June 14 in Florida. The Monank Patel-led side will hope to win their last fixture to seal their berth in the Super 8s as a loss will leave their fate in the hands of Pakistan. The Babar Azam-led side is on the third spot in Group A with one win from three matches. They will next face Ireland on June 16 and desperately need to win the last fixture and also have to hope for the USA's loss in their last game.

From Cristiano Ronaldo to Luka Modric: Stars playing their last UEFA Euro 2024

New Delhi. As the UEFA Euro 2024 beckons, European football stars like Cristiano Ronaldo, Luka Modric and Toni Kroos gear up for what could be their last dance in the top-tier European Championship. Top European international sides like England, France, Portugal and Spain are all set to battle it out in the upcoming UEFA Euro 2024, set to be hosted in Germany from June 15. The tournament will also see many star players extend their already massive international careers, while they battle out their experience with the young and rising names in the football structure. For starters, this UEFA Euro 2024 will mark the likes of Cristiano Ronaldo extending his phenomenal tally of playing the highest number of games in the competition in what will be his record-extending sixth European Championship. On the other hand, the likes of France will also walk into a new era with Euro 2024, under their new captain and star-forward Kylian Mbappe. Additionally, the three-time winners of the competition in Germany have further increased the hype around Euro 2024, after coach Julian Nagelsmann brought 34-year-old Toni Kroos back from retirement for the

tournament.

Luka Modric - Croatia

The Croatia skipper is one of the biggest names who is likely to take the field in this edition of the European championship for the last time, and will surely be at the centre of the sides' plans like many years and tournaments before. Luka Modric will walk into UEFA Euro 2024 as Croatia's most capped player, after his 175 appearances across all competitions, and arguably their best player since the last decade. Having already played a crucial part in leading Croatia to a runners-up finish in the 2018 FIFA World Cup, followed by a third-place finish in the 2021 World Cup, Modric will be eyeing his long-desired international title in what could be a swansong for the midfielder. The 38-year-old Real Madrid number 10 has already talked about his desire to continue with Los Blancos for at least one more year, but his international career might just meet an end in the Euro.

Toni Kroos - Germany

Modric's Real Madrid teammate and midfield partner Toni Kroos has set up an exciting opportunity for his last dance in the German jersey. Having already announced his

retirement from international football back in 2021, the 34-year-old's brilliant playmaking and top-notch site-piece abilities have been deemed a must-have yet again by coach Julian Nagelsmann. However, this has already been confirmed to be Kroos's last major tournament before his ultimate retirement from professional football. The iconic Los Blancos legend has already drawn curtains on his prestigious club career after clinching the 2023-2024 La Liga and the UEFA Champions League title for the sixth time, and has even confirmed that the UEFA Euro 2024 will also mark a second end to his international career. Cristiano Ronaldo - Portugal the biggest name on this list will surely be that of the five-time Ballon D'or and UEFA Euro 2016 winning Portugal superstar, Cristiano Ronaldo. At 39-years-old, Ronaldo will be walking into the European Championship for a record sixth time, and will yet again be one of Portugal's main attacking focuses. The Al Nassr forward has showcased some ageless brilliance everytime he has graced the competition, which even saw him clinch the Golden Boot winner in the 2021 edition of the competition.

Pat Cummins clarifies controversy around Australia manipulating result vs Scotland

Australian pacer Pat Cummins clarified the controversy around the team manipulating the result in the Scotland match. He affirmed that the Australian team's mindset and their approach won't change despite England's predicament. He also said that Josh Hazelwood's 'joke' on the easy-going approach against the Scotland team was taken out of context. Mitchell Marsh's Australian team had come under scanner with questions being raised on 'spirit of cricket' after Hazelwood's remarks. Australia will face Scotland in the Group B match on June 16, Sunday at the Darren Sammy National Cricket Stadium in St Lucia. Cummins suggested that Australia will look to put a tough fight against Scotland, who have a chance to qualify for the Super 8 stage.

"When you go out and play, you're trying your best every time. And if you're not, it's probably against the spirit of cricket," the

Test and ODI captain, who handed the reins to Marsh for the T20 side, told the media. "I haven't really thought too deeply because it's never really popped up." "I was speaking to Joshy who had a bit of a joke about it the other day and it got taken a bit out of context. We'll go out there and try to play Scotland who have had a really good tournament so far so it's going to be tough.

What Hazelwood said?

During the post-match press conference after the game against Namibia, Hazelwood was asked if they would go easy against Scotland. The pacer had said that the team had not had any discussions about it yet, but they would not rule out the possibility of this happening, knowing England could pose a major threat in the later stage of the tournament. Cummins pointed out that



Australia would never intend to under-perform in order to knock England out of the context. "It's something you discuss as one of the quirks of the setup, but it does it change the way we play? Absolutely not."

Will Australia manipulate result?

Hence, Scotland would need to beat Australia in order to edge past England in the Super 8 stage. Meanwhile, captain Marsh could face a ban if Australia manipulate Scotland's result to knock England out.



Anjum Fakih

In Bigg Boss OTT 3? Kundali Bhagya Star CONFIRMED For Anil Kapoor's Show

Television actress Anjum Fakih has confirmed her participation in the upcoming season of Bigg Boss OTT. News18 Showsha has exclusively learnt that the actress, who is known for her role in Kundali Bhagya, is all set to participate in Anil Kapoor's show. A source close to the actress told us that she has signed the project and will be entering the Bigg Boss OTT 3 house on June 21. However, neither Anjum nor the Bigg Boss OTT 3 team, have issued any official statement confirming her participation as of now.

Anjum Fakih is known for playing the role of Srishiti Arora Luthra in Kundali Bhagya, which also starred Shraddha Arya in the lead. However, she left the popular show in 2023 when she decided to participate in Khatron Ke Khiladi 13. Talking about her participation in the stunt-based reality show, the 33-year-old actress previously told us that Rohit Shetty's show helped her become a stronger person.

"When I used to watch Khatron Ke Khiladi in India, I used to feel all pumped up. But after I performed my first stunt, my confidence hit rock bottom. I was like, 'How will I do it?' I know that I am also weak. I may be six feet tall but I am very sensitive. But here, I have performed so many stunts already. I think I have performed the maximum number of stunts. I have become stronger now. I will walk forward with a 'Khiladi wala attitude' now. The battle scars from the stunts will be in my memories. It shows that if I can do this, I can do anything in life," she said.

Meanwhile, Bigg Boss OTT 3 will premiere on June 21, 2024. This year, the show will be hosted by Anil Kapoor. Among others, Mika Singh, Tanushree Dutta, Mithun Chakraborty's son Ushmei Chakraborty, Hema Malini's daughter Ahana Deol and Sanjay Dutt's daughter Trishala Dutt have also been reportedly approached for Bigg Boss OTT 3. Reportedly, Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah fame Bhavya Gandhi is also in talks with the makers. It is also being said that the Imlie actor Sai Ketan Rao has been finalised for the upcoming season of Bigg Boss OTT.



Mahesh Babu Names The Film He Has Watched A 100 Times



Mahesh Babu is a very influential name in the film industry. He is someone who has starred in some of the biggest, record-breaking films in the Telugu film industry. But there is one film the actor is a huge fan of, which he has watched almost 100 times. The Guntur Kaaram actor was recently involved in a promotional event for Sudheer Babu's upcoming release titled Harom Hara. During the event, the younger actor asked him which actor had mastered the art of handling guns. To this, Mahesh Babu took the superstar and his father Krishna's name and revealed that he has watched the 1971 film Mosagallaku Mosagadu 100 times. He said, "It is undoubtedly Superstar Krishna Garu. I would have watched Mosagallaku Mosagadu for more than 100 times." He further stated, "It is my favourite among my dad's films. There is no other actor in my mind."

Released in 1971, Mosagallaku Mosagadu was made under the direction of KSR Das while Aarudra was the writer. The film starred names like Krishna, Vijaya Nirmala, Nagabhushanam, Gummati, Kaikala Satyanarayana, M Prabhakar Reddy, Dhulipala and Jyothi Lakshmi. G Adishesagiri Rao produced the film under the banner of Padmalaya Studios while P Adinarayana Rao composed the music. The film was the first Telugu language cowboy release. It was heavily inspired by Western classics like For a Few Dollars More and The Good the Bad and the Ugly. It reportedly collected Rs 50 lakh at the box office on a budget of Rs 8 lakh. The film was also released in English dub with the title Treasure Hunt while a Tamil version was released as Mosakkaaranukku Mosakkaaran and the Hindi version was called Gunfighter Johnny. At the moment, Mahesh Babu is preparing for his upcoming project with SS Rajamouli, tentatively being called SSB29. The film is currently under pre-production and is expected to start filming this year. It is reportedly an adventure-drama which is being written by Vijayendra Prasad while the producer is K L Narayana of Durga Arts.

Triptii Dimri Looks Stunning As She Shares Glimpse Of Her Vacation In Italy, Fans React



Triptii Dimri enjoys a huge fan following. She is currently enjoying a vacation in Italy and shared a glimpse of her social handle. She is looking stunning in the video and fans have also reacted to it. The actress will be soon seen sharing screen space with Kartik Aaryan in Bhool Bhulaiyaa 3. Taking to her Instagram handle, Triptii shared a video in which we can see roaming around the city and enjoying the view. Many fans called her national crush. Recently, she grabbed headlines after she was seen in Ranbir Kapoor starrer Animal. The actress is fondly called National Crush. Recently, she also announced her next with Vicky Kaushal and Ammy Virk. Well, amid this Triptii was spotted with her rumoured boyfriend, Sam Merchant in the city. The lovebirds stepped out amid heavy rains, with their friends. They were spotted sharing giggles and laughter inside a car. A video shared by Filmgyan has gone viral on social media.

Earlier this month, Triptii Dimri was spotted holidaying with her rumoured boyfriend Sam Merchant at an undisclosed location. Triptii, whose intimate scenes in Ranbir Kapoor starrer Animal became the talk of the town and skyrocketed her popularity on Instagram from 888k followers to 5.1 million followers in just a few months, has been dating Sam for a while, according to multiple unconfirmed media reports. The actress took to her Instagram story and reposted Sam's story featuring a beautiful view of sunset. In her second story, Triptii also added a blue heart emoji over the photo of the sunset. The rumours about Triptii and Sam dating began when the latter shared a selfie with the actress from a wedding they were attending. While fans still believe that they could be dating, a source had told Zoom TV in December that Triptii was single. "Triptii-Sam rumour is plain hogwash. Triptii is very much single," the insider claimed. On the work front, Triptii is all set to work with Vicky Kaushal and Ammy Virk on Karan Johar's production, Bad Newz. The film will hit the theatres in July. Apart from Bad Newz, she will be seen in Kartik Aaryan's Bhool Bhulaiyaa 3. The film is slated for Diwali release.

Samantha Ruth Prabhu

Gearing Up For Her Malayalam Debut? What We Know

Samantha Ruth Prabhu has proved her mettle in the Telugu and Tamil film industries. Counted among the top actresses in the South Indian film industry, Samantha will reportedly soon widen her horizon as an artist as she plans to enter Malayalam cinema soon. Tamil director Gautham Vasudev Menon is reportedly making a Malayalam film with Mammootty. According to reports, Gautham Menon has decided to cast Samantha as the female lead in the film. Samantha and Gautham Menon had earlier collaborated in the huge blockbuster Ye Maaya Chesave, where the actress worked with her ex-husband Naga Chaitanya for the first time. It is also interesting to note that Samantha shared screen space with Mammootty earlier this year for an ad campaign for a company offering financial services. It is also reported that Nayanthara was initially roped in for the yet untitled Malayalam film with Mammootty but she left for unknown reasons and was replaced by Samantha. Samantha is said to begin the shoot on June 15 in Chennai, while Mammootty will be joining the sets on June 20. The movie will reportedly be an action thriller.



One of Samantha's peers in the Telugu film industry, Anushka Shetty is also foraying into Malayalam cinema with Kathanaar: The Wild Sorcerer, a fantasy thriller film. Krithi Shetty is also doing a Malayalam film Ajayante Randam Moshanam. Samantha most recently

appeared in Kushi opposite Vijay Deverakonda which was a moderate success at the box office. Samantha Ruth Prabhu will next appear in the Indian adaptation of Citadel alongside Varun Dhawan. Directed by Raj and DK, Citadel: Honey Bunny features a captivating narrative that combines the intense elements of a spy action thriller with the heartwarming charm of a love story, set against the vibrant backdrop of the 90s. Additionally, Samantha will star in Bangaram, where she plays a strong character. The first glimpse of this film has made a significant impression on cinephiles.

